सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 326, नई दिल्ली । रविवार, 04 फरवरी 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते।

03 'आप के सात विधायकों को खरीदने की कोशिश में भाजपा
06 भारत के हिन्दू मन्दिरों ने पर्यटन के पंख लगाये
08 मतदान से पहले पश्चिम ओडिशा 3 पार्टियों के फोकस में है

मार्च के अंत तक दौड़ने लगेंगी प्रीमियम बसें

दिल्लीवासियों को घर के पास मिलेगी यह सुविधा

अधिकारियों के अनुसार, जिस कंपनी को लाइसेंस मिलेगा, उसे कम से कम 25 बसों संचालित करना होगा। यह लाइसेंस पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा। बसें नौ सीट की इलेक्ट्रिक होंगी। बस का रूट और किराया कंपनी खुद तय करेगी।

संजय बाटला

दिल्ली सरकार की प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना के तहत बसें जल्द ही सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। एक कंपनी के आवेदन को फरवरी अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। योजना में तीन कंपनियां आवेग, चलो और उबर ने रुचि दिखाई है। इनमें दो के आवेदन मिल गए हैं, जबकि एक कंपनी का आवेदन नहीं आया है।

नईदिल्ली। अधिकारियों का कहना है कि एक कंपनी के आवेदन की फाइल परिवहन आयुक्त के पास भेजी गई है। बताया जा रहा है कंपनी को लाइसेंस मिलने के बाद मार्च अंत तक बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। अधिकारियों के अनुसार, जिस कंपनी को लाइसेंस मिलेगा, उसे कम से कम 25 बसों संचालित करना होगा। यह लाइसेंस पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा। बसें नौ सीट की इलेक्ट्रिक होंगी। बस का रूट और किराया कंपनी खुद तय करेगी।

लाइसेंस देने के बाद परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बसें नियमों के दायरे में चल रही है यह नहीं। नियमों के उल्लंघन पर इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन बसों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूप भी बनाया जाएगा। इसमें बस यात्रा आदि का डाटा रखा जाएगा। बता दें कि गत वर्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नवंबर में एलजी वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद मोबाइल ऐप आधारित प्रीमियम बस योजना लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी।

घर के पास मिलेगी सुविधा

प्रीमियम बसें वहीं उपलब्ध होगी, जहां से यात्रियों ने टिकट बुक करवाया है। बशर्ते यात्री को प्रीमियम बस के रूट पर ही चलना हो। इसके लिए उसे सड़क के बस स्टॉप तक नहीं जाना पड़ेगा। बस उसी लोकेशन पर रुकेगी, एप पर जहां से टिकट लिया गया है। बस में यात्री को कार की तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे रोजाना कार से दफ्तर तक जाने वाले लोग खुद ही इन बसों की सवारी करेंगे। इससे सड़कों से कारें हटेंगी, जिसका नतीजा जाम व प्रदूषण में कमी के तौर पर रहेगा।

इन क्षेत्रों में बनाया जा सकता है रूट

द्वारका, रोहिणी, वसुंधरा एन्क्लेव, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, ग्रीन पार्क, हौज खास, लक्ष्मीबाई नगर, आईएनए, चाणक्यापुरी, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, सिविल लाइंस, बुराड़ी, करोल बाग, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, महिपालपुर समेत कई क्षेत्रों में इन बसों का रूट बनाया जा सकता है।

दैनिक यात्रियों को मिलेगा फायदा

इस योजना से नौकरीपेशा लोगों को खास फायदा होगा। जो लोग कार से अपने दफ्तर जाते हैं, उनको कार छोड़ने का बेहतर विकल्प मिलेगा। अगर रोहिणी की किसी

कॉलोनी के सात-आठ लोग रोजाना कनॉट प्लेस स्थित अपने दफ्तर कार से जाते हैं तो वह प्रीमियम बस बुक कर सकेंगे। बस उनके घर पर आएगी और उन्हें उनके कार्यालय पर छोड़गी। यह बसें सामान्य बसों से छोटी होंगी, ऐसे में जहां पर सामान्य बसें नहीं जा सकती है, वहां पर इन बसों की सेवा ली जाएगी।

नेहरू प्लेस बस टर्मिनल बनेगा अत्याधुनिक, 12 मंजिला होगा

नेहरू प्लेस के नजदीक स्थित बस टर्मिनल को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अत्याधुनिक बनाएगा। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत नेहरू प्लेस के वर्तमान बस टर्मिनल का कायाकल्प कर 12 मंजिला अत्याधुनिक बस डिपो तैयार करेगा। इसके लिए टेंडर निकाला जा चुका है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसमें व्यावसायिक कांप्लेक्स व मॉल भी बनेंगे। इससे नेहरू प्लेस बस टर्मिनल व्यावसायिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनेगा। डीएमआरसी ने निजी क्षेत्र की एजेंसियों से आवेदन मांगे हैं। अधिकारियों के अनुसार, 17 जून 2022 में नेहरू प्लेस बस टर्मिनल के आधुनिकीकरण के लिए डीटीसी व डीएमआरसी के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत इस पांच बस टर्मिनलों के निर्माण करने की जिम्मेदारी डीएमआरसी को दी गई है। इसके मद्देनजर डीएमआरसी ने इस बस डिपो के आधुनिकीकरण के लिए पहल की है। बस टर्मिनल में व्यावसायिक कांप्लेक्स के अलावा पार्किंग की भी सुविधा होगी। साथ ही, इसे मल्टी मॉडल इंटिग्रेशन सिस्टम के तहत मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा।

पांच मंजिला पार्किंग भी बनेगी

नेहरू प्लेस बस टर्मिनल डिपो में 15749 वर्गमीटर जमीन है। इसके 7735 वर्गमीटर जमीन पर बस टर्मिनल के लिए 12 मंजिला भवन बनेगा। भूतल पर बस टर्मिनल, इसके बाद एक से पांच मंजिल तक पार्किंग और ऊपर सात मंजिल (6 से 12 मंजिल तक) का व्यावसायिक कांप्लेक्स बनेगा।

1. Web Portal https://www.newsparivahan.com/
2. facebook https://www.facebook.com/newsparivahan00
3. Twitter https://twitter.com/newsparivahan
4. Linkedin https://www.linkedin.com/in/news-parivahan-169680298/
5. Instagram https://www.instagram.com/news_parivahan/
6. Youtube https://www.youtube.com/@NewsParivahan

पर आप सभी के लिए 24 घण्टे उपलब्ध

3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, A-4 पश्चिम विहार, नई दिल्ली : 110063
सम्पर्क : 9212122095, 9811732095

www.newsparivahan.com, www.newstransport.in
Info@newsparivahan. com, news@newsparivahan.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

उत्तराखंड के साथ होगा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, सीटीयू 4666 किमी तो उत्तराखंड 2052 किमी चलाएगा बस

परिवहन विशेष न्यूज

यूटी प्रशासन ने आखिरी बार वर्ष 2008 में पंजाब के साथ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट किया था। उसके बाद अब उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया जा रहा है। चंडीगढ़ के आईएसबीटी-17 और आईएसबीटी-43 से हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब के लिए बसें चलती है।

चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन पहली बार उत्तराखंड सरकार के साथ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट करने जा रहा है। प्रशासन ने समझौते का मसौदा तैयार कर लिया है और शहर की जनता से इस पर सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं।

मसौदे के अनुसार उत्तराखंड में सीटीयू 4666 किमी तो उत्तराखंड, चंडीगढ़ में 2052 किमी चलाएगा। वर्तमान में आपसी समझौते के आधार पर बसें चल रही हैं। इसके साथ ही प्रशासन पहली बार हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, यूपी, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली सरकार के साथ भी रेसिप्रोकल एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है और पत्र भेजे गए हैं।

मसौदे की कॉपी परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट chdctu.gov.in पर समीक्षा के लिए उपलब्ध है। शहरवासी 30 दिन के अंदर सेक्टर 9 स्थित चंडीगढ़ सचिवालय की दूसरी मंजिल पर मौजूद परिवहन सचिव के दफ्तर में जाकर अपने सुझाव व आपत्तियां जमा कर सकते हैं या hs-chd@nic.in पर इमेल भी कर सकते हैं।

यूटी प्रशासन ने आखिरी बार वर्ष 2008 में पंजाब के साथ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट किया था। उसके बाद अब उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया जा रहा है। चंडीगढ़ के आईएसबीटी-17 और आईएसबीटी-43 से हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब के लिए बसें चलती है। इनमें से सिर्फ पंजाब के साथ 2008 में समझौता हुआ था। उसे भी अब संशोधित करने की जरूरत है। इसके अलावा अन्य राज्यों के साथ समझौता के लिए यूटी प्रशासन पिछले काफी समय से कोशिश कर रहा है लेकिन राज्य की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है।

प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ की तरफ से विभिन्न राज्यों को रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के लिए कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं। रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की वजह से एग्रीमेंट नहीं बन पाया है। उन्होंने बताया एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से आपसी समझौते के आधार पर बसें चल रही हैं।

नमो भारत रैपिड रेल : NCRTC का एलान, स्टेशनों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम, बनेगी बिजली; कम होगा प्रदूषण

परिवहन विशेष न्यूज

एनसीआरटीसी ने कहा कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीसी के स्टेशनों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाने की तैयारी है। इससे खुद की बिजली बनेगी। इसी तरह से दिल्ली मेट्रो ने भी अपने स्टेशनों पर इसी तरह से रूफटॉप सोलर लगाए हुए हैं।

नईदिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने बड़ा ऐलान किया है। एनसीआरटीसी ने कहा कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीसी के स्टेशनों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इससे बिजली बनाई जाएगी और सीओ2 एमिशन कम होगा। शनिवार को इसकी जानकारी दी गई।

ये रूफटॉप सिस्टम साहिबाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो स्टेशन और दुहाई वर्कशॉप में आरआरटीएस स्टेशनों के प्लेटफॉर्म शेड पर लग चुके हैं। जिससे लगभग तीन मेगावाट की सौर क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है, जो इन स्थानों की सहायक लोड आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगी।

शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, इस साल कटेंगे चार गुना चालान

गुरुग्राम में शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। इस साल शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर चार गुना चालान काटने का लक्ष्य रखा गया है। जहां पिछले साल 12 महीनों में 5000 वाहन चालकों के चालान किए गए थे। इधर 2024 में इस एक महीने में ही 1000 से ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान काटकर यातायात पुलिस ने कड़ा संदेश दिया है।

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। इसे गुरुग्राम पुलिस की एडवाइजरी समझ लें या नसीहत, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक सावधान हो जाएं। इस साल शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर चार गुना चालान काटने का लक्ष्य रखा गया है। जहां पिछले साल 12 महीनों में 5000 वाहन चालकों के चालान किए गए थे। इधर 2024 में इस एक महीने में ही 1000 से ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान काटकर यातायात पुलिस ने कड़ा संदेश दिया है।

शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाने से कई हादसे हुए हैं। पिछले साल अगर हादसों की बात करें तो 1100 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। वहीं 400 सौ से ज्यादा लोगों की इन दुर्घटनाओं में मौत हो गई। साथ ही कई बार तो नाके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों का निशाना बने हैं। सितंबर में इफको चौक के पास एक नाके पर तैनात होमगार्ड की भी मौत गाड़ी की टक्कर से हुई थी।

इन सभी चीजों को देखते हुए पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने इस साल यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस आयुक्त ने 2024 में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत इसका लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। 15 से 20 हजार चालान इस बार सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव के काटे जाएंगे। वहीं यातायात पुलिस ने पहले ही महीने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 1032 वाहन चालकों का चालान कर अपना इरादा साफ कर दिया है।

चार गुना नाके भी लगाए जा रहे

पुलिस आयुक्त के निर्देश पर यातायात पुलिस के साथ-साथ जोनल पुलिस को भी सक्रिय किया गया है। जहां शहर भर में पिछले साल तक ड्रिंक एंड ड्राइव के सिर्फ 8 से 10 नाके लगाए जा रहे थे। वहीं इस साल की शुरुआत से ही इनमें चार गुनी तक बढ़ोतरी की गई है। अब जोनल पुलिस भी अपने-अपने जोन में ड्रिंक एंड ड्राइव के नाके लगा रही है। शहर में तीन दिन बुधवार, शुक्रवार और शनिवार रात को स्पेशल अभियान चला कर ड्रिंक एंड ड्राइव के नाके लगाए जा रहे हैं। यहां पर ढाई सौ से तीन सौ पुलिसकर्मियों को लगाया गया है।

“

यातायात के नियमों के उलंघन करने पर गुरुग्राम पुलिस काफी सख्त है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोग सावधान हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ जोनल पुलिस भी इस बार कड़ा अभियान चलाएगी और चार गुना तक चालान किए जाएंगे।

– विकास अरोड़ा, पुलिस आयुक्त

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

प्राचीन भारत में नारी...

प्राचीन भारतीय समाज में नारियों का सम्मान और आदर आदर्श रूप में था। वह माता पत्नी पुत्री बहन आदि के रूप में परिवार में आदृत थी। समाज उसके प्रति श्रद्धा और आस्था रखता था। धर्म शास्त्रों में तो शक्ति रूप में आस्था की विषय वस्तु थी। इन सब के बाद भी प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति सदैव सामान नहीं रही। विभिन्न कालों मे उनकी स्थिति परिवर्तनशील थी। संक्षेप में उनकी विभिन्न कालों में स्थिति का विवरण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

सैधव सभ्यता युगीन नारी:

भारत के प्राचीनतम माने जाने वाली सेंधव सभ्यता में नारियों की स्पष्ट स्थिति जानने के स्रोत उपलब्ध नहीं है। विभिन्न पूरा स्थलों से प्राप्त पूरा अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने उनकी स्थिति का आकलन किया है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा चन्हूदरो आदि स्थलों से नारियों की मृण्मूर्तियां बहुतायत रूप से प्राप्त हुई हैं। सर जान मार्शल अर्नेस्ट मैके ने इन नारी मूर्तियो के आधार पर यह स्थापित किया कि उस समय मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था। कतिपय मूहरो पर नारी के सर्जनात्मक शक्ति को प्रतिको के रूप में भी दर्शाया गया है। इस आधार पर नारी के सुखद पूज्य और गरिमामय स्थिति का अनुमान किया जा सकता है।

महाकाव्यो में नारी:

महाकाव्यो में नारी के अच्छे और बुरे दोनों स्थितियों के दर्शन होते हैं। उनकी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगा था। रामायण में सीता और महाभारत में द्रौपदी कुंती माद्री का विवरण इस का उदाहरण है। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में उनका योगदान था। महाभारत के अनुसार उनकी अनुपस्थिति में सारे कार्य अपूर्ण हैं। रामायण में आया है कि अश्वमेध में राम को सीता की अनुपस्थिति से स्वर्ण प्रतिमा रखनी पड़ी। इस युग में नारी पूजा पूर्णतया प्रतिष्ठित थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी नारिया अग्रणी थी। कुंती द्रौपदी उत्तरा कैकेयी ही आदि उच्च शिक्षित महिलाएं थी। इन सब के बाद भी नारी वस्तु हो गई थी इसे धनादि के साथ जूए में हारा जीता जाता था।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक:

बौद्ध ग्रन्थो में नारियों की स्थिति के दर्शन होते थे। संयुक्त निकाय में कहा गया है कि गुणवती कन्या को पुत्र से भी अच्छा समझना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इनका सहयोग महत्वपूर्ण था। विद्या धर्म और दर्शन के प्रति उनकी अगाध रुचि थी। थेरी गाथा में 32 ब्रह्माचारिणी 18 विवाहित भिक्षुणीयो का वर्णन है। नारियां बौद्ध आगमों की शिक्षिका के रूप में विख्यात थी। शुभा सुमेधा खेमा अनोपम सुभद्रा भद्रकुण्केशा ऐसी नारियां थी जिनकी विद्वता दूर-दूर तक विख्यात थी। जैन साहित्य भी ऐसी नरियों के वर्णन से भरे हैं। कौशांबी नरेश की पुत्री जयन्ता ज्ञान और दर्शन में पारंगत थी। पाणिनि सूचित करते हैं की नारियां शिक्षिका के रूप में भी जीवन चलाती थी। यह उपाध्याया कही जाती थी। महिला शिक्षा शालाओं का उल्लेख पणिनि ने किया है। इस काल में स्त्रियों को कुछ हीन समझा जाता था। बुद्ध ने बड़ी कठिनता से उन्हें संघ में प्रवेश की आज्ञा दी।

मौर्य उत्तर एवं गुप्त काल तक:

मौर्य के बाद और गुप्तों के कल तक स्थिति में परिवर्तन हो चुका था। अधिकांश स्मृतियों में उनकी स्थिति अत्यंत निम्नतर हो गई थी। इसा पूर्व दूसरी सती तक उपनयन वेद अध्ययन आदि संस्कार उनके लिए वर्जित कर दिए गए। मनु के शब्दों में पति ही कन्या का आचार्य विवाह, उनका उपनयन पति सेवा ही उनका आश्रम और गृह के कार्य ही उनके धार्मिक अनुष्ठान है उन्हें शूद्रों की कोटि में खड़ा कर दिया गया। इस संबंध में सभी स्मृतिकार एकमत है स्मृतियों मे उनकी आलोचना की गई। उन्हें स्वतंत्रता के योग्य नहीं माना गया। मनु ने लिखा। लेकिन व्यवहार में उनका आदर भी था। मनु ने ही लिखा है कि र्यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंते तत्र देवताः अर्थात जहां नारियो की पूजा होती है वहां देवता विचरण करते हैं। पतंजलि ने भी शिक्षिकाओं का वर्णन किया है। पुराणों में हमें दोनों स्थितियों के दर्शन होते हैं। पुराणों में भुवना अपर्णा एकवर्णा एक पाटला मेना धारिणी आदि अनेक ब्रह्मवादिनी और विदुषी नारियों का वर्णन है। ललित कलाओं में भी ये पारंगत थी। लेकिन नारियों से संबंधित अधिकांश कुरीतिया भी इस कल तक उत्पन्न हो चुकी थी, जैसे बाल विवाह, विधवा, दासी, नारी परतंत्रता आदि अभिजात वर्ग में पर्दा प्रथा प्रारंभ हो गया। भृच्छकटिकम ललितविस्तार आदि में उदाहरण मिलते हैं। उनको संपत्ति के अधिकार तो थे लेकिन पुरुषों के बाद ही इनके दायाधिकार की गणना की जाती थी।

गुप्तोत्तर काल में नारी600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक:

पूर्व मध्यकाल में नारियों की स्थिति रूढियो में फस गई थी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों ने समाज को आच्छादित कर दिया। टीकाकरण मेघातिथि विज्ञानेश्वर विश्वरूप अपरार्क ने नारी के लिए गृह शिक्षा की ही व्यवस्था रखी। अभिजात वर्ग से ही उच्च शिक्षित महिलाएं उदित होती थी। पुत्रियां दुख समझी जाने लगी। कथा सरित्सागर के अनुसार पुत्र सुख का प्रतीक और पुत्रियां दुख का मूल है। यधपि कुछ विदुषी और राजशास्त्र में प्रवीण नारियों के उदाहरण भी प्राप्त है। रेखा रोहा माधवी अवंती सुंदरी मंडनमिश्र की पत्नी प्रभावती गुप्ता राजश्री नैनिका दिद्दा सुगंध अक्का देवी भैला देवी जैसी कवित्रियों और शासिकाओं के वर्णन मिलते हैं। इस युग में वेश्यावृत्ति का भी प्रसार हुआ संपत्ति के अधिकार स्मृतियों के समान ही रहे।

स्किन और हेल्थ का रखना है ख्याल, हैंडबैग में कैरी करें ये 5 चीजें, सर्दियों में भी रहेंगी फिट और फाइन

सर्दियों का मौसम कई लोगों का फेवरेट होता है. हालांकि सर्दियों में त्वचा और सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी हो जाता है. ऐसे में जहां ठंडी हवाओं के चलते स्किन डल और ड्राई नजर आती है. तो वहीं सर्दी से बचने के लिए कुछ चीजें भी साथ में रखनी पड़ती है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं सर्दियों (Winter tips) के कुछ जरूरी सामान, जिन्हें घर से निकलते समय आप अपने हैंडबैग में कैरी कर सकती हैं. इससे आपको सर्दी में कोई भी परेशानी नहीं होगी.

मॉइश्चराइजर रखें: सर्दियों के मौसम में त्वचा जल्दी रुखी हो जाती है. ऐसे में सिर्फ एक बार मॉइश्चराइजर लगाना काफी नहीं होता है. इसलिए घर से निकलते समय हैंडबैग में मॉइश्चराइजर रख लें. वही हर थोड़ी देर में हाथों और पैरों सहित अन्य बॉडी पार्ट्स पर मॉइश्चराइजर अप्लाई करें. इससे आपकी स्किन हमेशा सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी.

लिप बाम लगाएं: सर्दियों का असर होंठों पर भी देखने को मिलता है. ऐसे में ड्राइनेस के चलते होंठ फटने लगते हैं. इसलिए हैंडबैग में लिप बाम कैरी करना भी जरूरी होता है. वहीं लिप बाम की जगह आप वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. साथ ही समय-समय पर इसे लगाकर आप ना सिर्फ होंठों को फटने से रोक सकती हैं बल्कि लिप्स को मुलायम भी रख सकती हैं.

टिशू पेपर साथ रखें: घर से निकलते समय रुमाल तो अमूमन सभी रखते हैं. मगर आप हैंडबैग में कुछ टिशू पेपर भी डाल सकती हैं. वहीं खांसी या छींक आने पर आप इन टिशू पेपर का यूज करके उन्हें फेंक सकती हैं. जिससे आपकी रुमाल गंदी नहीं होगी और हाइजीन भी मेंटेन रहेगा.

वॉटर बॉटल कैरी करें: ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है. ऐसे में कम पानी पीने से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है. इसलिए हैंडबैग में एक वॉटर बॉटल जरुर कैरी करें. वहीं आप गर्म पानी की बोतल भी बैग में रख सकती हैं. जिससे आप हर थोड़ी देर में पानी पी सकेंगी और आपको ठंड भी नहीं लगेगी.

वॉटर बॉटल कैरी करें: ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है. ऐसे में कम पानी पीने से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है. इसलिए हैंडबैग में एक वॉटर बॉटल जरुर कैरी करें. वहीं आप गर्म पानी की बोतल भी बैग में रख सकती हैं. जिससे आप हर थोड़ी देर में पानी पी सकेंगी और आपको ठंड भी नहीं लगेगी.

स्कार्फ-ग्लव्स रखें: सर्दियों के दौरान घर से बाहर निकलते समय हैंडबैग में स्कार्फ और ग्लव्स जरूर रख लें. ऐसे में हवा से बचने के लिए आप स्कार्फ और ग्लव्स पहन सकती हैं. जिससे आपको सर्दी नहीं लगेगी और आप ठंड से बची रहेंगी.

सनस्क्रीन अप्लाई करें: सर्दियों में ज्यादातर लोग सनस्क्रीन लगाना अवॉयड करते हैं. सर्दी की धूप बेशक काफी हल्की होती है. लेकिन इनमें मौजूद यूवी रेज त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसलिए हैंडबैग में सनस्क्रीन रखना ना भूलें. वहीं हर 3-4 घंटे बाद त्वचा पर सनस्क्रीन लगाती रहें. जिससे आपकी त्वचा धूप से सुरक्षित रहेगी।

आखिर गर्भवती महिलाओं का सर्दियों में आहार कैसा हो? गलत खान-पान स्वास्थ पर कैसे डालता है प्रभाव?

वैसे तो गर्भवती महिलाओं को हर मौसम में अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ठंड में अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है. दरअसल, सर्दियों में हमारा स्वास्थ्य अन्य मौसम की तुलना में अधिक संवेदनशील हो जाता है. ऐसे में त्वचा को हाइड्रेट रखकर इम्युनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग रखना बेहद जरूरी होता है. हालांकि, यह सब तभी संभव होगा, जब गर्भवती महिला पौष्टिक आहार ले. ऐसा करने से पेट में पल रहा शिशु भी स्वस्थ्य रहेगा. आइए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा से जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान ठंड में किन चीजों का सेवन करना चाहिए?

ा को हाइड्रेट रखकर इम्युनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग रखना बेहद जरूरी होता है. हालांकि, यह सब तभी संभव होगा, जब गर्भवती महिला पौष्टिक आहार ले. ऐसा करने से पेट में पल रहा शिशु भी स्वस्थ्य रहेगा. अब सवाल है कि आखिर गर्भवती महिलाओं का सर्दियों में आहार कैसा हो? गलत खान-पान स्वास्थ पर कैसे डालता है प्रभाव? इन सवालों के बारे में बता रही हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा-

सर्दियों के लिए गर्भवती महिलाओं का पौष्टिक आहार

फल और सबज़ियां खाएं: सर्दियों के मौसम में गर्भवती महिलाओं को विटामिन सी से युक्त फल जैसे संतरा, सेब, केला का सेवन जरूर करना चाहिए. ये फल शरीर में इम्युनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं. साथ ही ठंड में पालक, सलाद, पत्ता, फूलगोभी और हरी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए. ऐसा करने से मां और बच्चा दोनों हेल्दी रहेंगे.

क्या है गैसट्रिक स्लीव सर्जरी? जो मिनटों में कम कर देता है मोटापा आगे देखें...

उचित मात्रा में आयोडीन लें: गर्भावस्था के दौरान आयोडीन से युक्त चीजों को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. क्योंकि, आयोडीन की कमी आपके बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में जरूरी है कि उचित मात्रा में अंडे, समुद्री भोजन, नमक आदि जरूर खाएं. ऐसा करने से जच्चा-बच्चा दोनों का स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा.

खुद को हाइड्रेट रखें: ठंड में गर्भवती महिलाओं को हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी होता है. इसके लिए जरूरी है कि अच्छी मात्रा में पानी पीएं. इसके अलावा, आप फलों और सब्जियों का ताजा रस, नींबू पानी, छाछ आदि का भी सेवन कर सकती हैं. ऐसा करने से आप खुद को बीमारियों से दूर रख पाएंगी.

कैल्शियम-फाइबर जरूरी: प्रग्नेंसी में हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम-फाइबर युक्त चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए. इसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट, अनाज, दालों का डाइट में शामिल कर सकते हैं. दरअसल, ये चीजें तमाम पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. इसलिए नियमित डेयरी प्रोडक्ट की 3 से 4 सर्विंग्स लें. वहीं, फाइबर युक्त चीजें कब्ज से छुटकारा दिलाने का काम करती हैं.

ठंड में ये एहतियात जरूरी

– गर्भवती महिलाओं को फ्लू का टीका जरूर लगवाना चाहिए.

– अत्यधिक ठंड में घर के अंदर रहें और पर्याप्त ऊनी कपड़े पहनें.

– डाइट में पालक, अदरक, आंवला, बादाम, दही, लहसुन, दूध, शिमला मिर्च और ब्रोकोली शामिल करें.

– शुष्क सर्दियों की हवा से शरीर को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है. इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

– हल्के व्यायाम जैसे चलना या सरल योग करें. ऐसा करने से आप और आपका बच्चा दोनों हेल्दी रहेंगे.

मोहल्ला क्लीनिक घोटाला: 65 हजार 'घोस्ट' मरीजों की हुई जांच, सिर्फ कागजों में दर्ज; दो लैब्स की सांठगांठ

परिवहन विशेष न्यूज

एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रारंभिक जांच में मोहल्ला क्लीनिक में टेस्ट करवाने आए 65 हजार से अधिक मरीज फर्जी पाए गए हैं। इस जांच के लिए दो निजी डायग्नोस्टिक लैब की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।

नई दिल्ली। अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक में हुए परीक्षण को लेकर एसीबी जांच कर रही है। इसकी प्रारंभिक जांच में दो निजी डायग्नोस्टिक लैब की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इनमें एगिलस डायग्नोस्टिक और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर शामिल है।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान दोनों निजी प्रयोगशालाओं में करीब 22 लाख परीक्षण किए गए। इसके बदले दिल्ली सरकार ने 4.63 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इन जांच में 65 हजार से अधिक परीक्षण फर्जी पाए गए हैं। इन प्रत्येक परीक्षण को करने में 100 से 300 रुपये का खर्च आया है।

एसीबी ने जांच के दौरान पाया कि परीक्षण के दौरान जिन मरीज के फोन नंबर दिए गए हैं। उनपर कॉल करने से चौकाने वाले तथ्य मिले। काफी लोगों ने बताया कि वह कभी जांच करवाने भी नहीं गए। साथ ही यह भी पता चला कि 63 फीसदी ने न तो कोई परीक्षण करवाया था, न ही किसी मोहल्ला क्लीनिक में जांच करवाने गए।

एसीबी ने किया फोन नंबर की जांच

एसीबी ने दोनों निजी प्रयोगशालाओं में आए मरीजों के सैंपल पर लिखे मोबाइल नंबरों में से कुछ नंबरों को चुना। फिर उन नंबर पर कॉल कर टेली-सत्यापन किया। इसमें पता चला कि बड़ी संख्या में मरीज परीक्षण करवाने नहीं आए। कई नंबर बंद मिले। कई अमान्य और काफी नंबर मरीजों से संबंधित नहीं थे। मरीजों की जांच से पता चला कि वे कभी भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए और न ही कोई जांच कराई।

बड़े स्तर पर की गई हेराफेरी

जांच में पता चला कि तथ्यों को छुपाने के लिए मरीजों के मोबाइल नंबर के नाम वाली लैब प्रबंधन सूचना प्रणाली (एलआईएमएस) भी विकसित की गई। इसे संचालित कर सुविधाजनक रूप से हेरफेर की कोशिश की गई। जांच में पाया गया है कि दो निजी विक्रेताओं के पास डेटा और सिस्टम सॉफ्टवेयर पर पूर्ण नियंत्रण था। इसकी मदद से डेटा में हेरफेर की आशंका है। इसे लेकर आउटसोर्स किए गए लैब विक्रेताओं द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता।

जांच में यह मिला आंकड़ा

एगिलस डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड (फरवरी 2023 से नवंबर 2023)
- बिना फोन नंबर के जांच - 12457 टेस्ट
- 0 मोबाइल नंबर के साथ जांच - 25732 टेस्ट
- 1,2,3,4,5 से नंबर से जांच - 913 टेस्ट
- एक नंबर को 80 बार इस्तेमाल - 2467 टेस्ट

मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर (फरवरी 2023 से दिसंबर 2023)
- मोबाइल नंबर 9999999999 पर जांच - 6121 टेस्ट (फर्जी नंबर)
- 9821749455 नंबर पर जांच - 2399 टेस्ट (नहीं करवाया कोई जांच)
- 11350 मोबाइल नंबर से जांच - 130 से अधिक बार

तेज होगी राजनीति

मोहल्ला क्लीनिक को लेकर दिल्ली में आने वाले दिनों में राजनीति तेज होगी। दिल्ली सरकार ने इसे विशेष तौर पर तैयार किया है। साथ ही चुनाव में इसका प्रचार भी किया। वहीं जांच के बाद आए तथ्यों को लेकर भाजपा भी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर राजनीति तेज हो सकती है।

ट्रिपल मौत से दहली दिल्ली: मकान में संदिग्ध हालात में पड़े थे तीनों, मृतकों में दो भाई और एक घरेलू सहायक

नई दिल्ली। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में दो भाइयों सहित तीन लोगो की संदिग्ध हालात में मौत होने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से लगाता है कि फूड पॉइजनिंग से इनकी मौत हुई है। मृतकों की पहचान अमित और सोनू के रूप में हुई है। मरने वाला तीसरा घरेलू सहायक है। दोनों भाई इलाके में छोले भटूरे की रेहड़ी लगाते थे। तीनों किराए के मकान में अचेत मिले थे, पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।

सीएम केजरीवाल को नोटिस देकर लौटी दिल्ली पुलिस, 'कौन हैं वो सात विधायक..., तीन दिन में दें जवाब'

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को फिर नोटिस देने के लिए सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंची। भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस बीते दिन मुख्यमंत्री को नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन मुख्यमंत्री सामने नहीं आए थे।

भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को भी सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर नोटिस देने पहुंची। नोटिस देने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास से निकलते हुए दिखी। पुलिस ने तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम बीते दिन भी नोटिस देने के लिए केजरीवाल के घर पहुंची थी।

दिल्ली पुलिस गुरुवार को मुख्यमंत्री को ही नोटिस देने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री सामने नहीं आए और अधिकारी नोटिस लेने की जिद करने लगे। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम वापस आ गई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नोटिस मुख्यमंत्री को ही दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्र के मुताबिक, सीएम ऑफिस नोटिस लेने के लिए तैयार है। लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम ऑफिस को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को ही नोटिस देने की बात कह रही है। सीएम ऑफिस का दावा है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को बस मीडिया में माहौल बनाने के लिए बोला गया है।

आप नेता और क्राइम ब्रांच की टीम के बीच हुई बहस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर नोटिस देने पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में बहस हुई। आप नेता जैस्मिन शाह ने कहा कि किसी भी कानून में यह नहीं लिखा हुआ है कि नोटिस सीधा मुख्यमंत्री को ही दिया जाना चाहिए। पुलिस महज सनसनी फैलाने के लिए इस प्रकार की कोशिश कर रही है।

कल आतिशी के घर भी पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार शाम दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के सरकारी आवास पर भी नोटिस देने पहुंची थी। आतिशी के चंडीगढ़ में होने के कारण पुलिस उन्हें भी नोटिस नहीं दे पाई। शनिवार को फिर पुलिस नोटिस देने पहुंच सकती है। नोटिस में पुलिस ने दोनों से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के साक्ष्य सहित अन्य जानकारी मांगी है।

एम्स करेगा खोज: अगर आप करते हैं धूम्रपान... उम्र है 50 के पार तो AIIMS को है आपकी तलाश, लोगों से की अपील

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स फेफड़ों के कैंसर के प्रारंभिक निदान के लिए अध्ययन करेगा। इसके लिए एम्स को धूम्रपान करने वाले 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की तलाश है। साथ ही लोगों से अपील भी की है।

नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ते फेफड़ों के कैंसर की पकड़ को आसान बनाने के लिए एम्स शोध करेगा। इस शोध में मरीजों को शामिल करने के लिए एम्स ने धूम्रपान करने वाले 50 साल से अधिक उम्र के लोगों से अध्ययन में शामिल होने की अपील की है।

इस शोध को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मरीजों पर लो डोज सीटी स्कैन को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जांच की जाएगी। पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों ने बताया कि फेफड़ों का कैंसर देश में तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल भारत में करीब एक लाख मामले सामने आए। लास्ट स्टेज में इसकी पकड़ होने के कारण मरीज औसतन 8.8 महीने ही जीवित रह पाते हैं।

इस समस्या को देखते हुए एम्स के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन विभाग ने धूम्रपान करने वाले मरीजों में शुरुआती चरण में फेफड़ों के कैंसर का पता लगाने के लिए पायलट अध्ययन शुरू किया है।

इस अध्ययन के दौरान मरीजों में छाती लो डोज सीटी स्कैन किया जाएगा। यह पूरी तरह से निशुल्क होगा। इस अध्ययन का हिस्सा बनने वाले इच्छुक व्यक्ति एम्स से संपर्क कर सकते हैं। इनमें उन्हीं लोगों की जांच होगी जो अत्यधिक धूम्रपान करते हो और उनकी उम्र 50 साल से अधिक हो। ऐसे व्यक्ति सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एम्स में 9821735337 फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित; ED ने धन शोधन मामले में किया था गिरफ्तार

राउज एवेन्यू अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार व्यवसायी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले में अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी।

नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को व्यवसायी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कात्याल को ईडी ने नौकरी के बदले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। उन्होंने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अमित कात्याल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। उनके आवेदन का ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन के साथ वकील मनीष जैन ने विरोध किया। अदालत इस याचिका पर पांच फरवरी को फैसला सुनाएगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल आठ जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की थी। उसमें अमित कात्याल, राबड़ी देवी, मीशा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और दो कंपनियों (एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड तथा एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) को आरोपी बनाया गया था। उसके बाद कोर्ट ने 27 जनवरी को पीसी का संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को आगे की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया।

'सनातन धर्म क्या है' : धीरेंद्र शास्त्री ने किया पुस्तक का विमोचन, बोले - हमारा धर्म इंसान को इंसान बनाता है

दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 'सनातन धर्म क्या है' पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेता भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इंसान को इंसान बनाता है। धर्म धारणा का विषय, प्राण है।

नई दिल्ली। सनातन धर्म इंसान को इंसान बनाता है। धर्म धारणा का विषय, प्राण है। सभी धर्मों से सनातन धर्म सर्वोपरि है। इसका ज्ञान विशुद्ध है, जान लेना ज्ञान है और प्रकट करना विज्ञान है। लेकिन, अधिकतर युवाओं से लेकर बुजुर्गों को सनातन के सिद्धांत का पता नहीं है।

यह बातें बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अपनी पुस्तक 'सनातन धर्म क्या है' के विमोचन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी का जीव हिंसा धर्म है, तो अहिंसा सनातन धर्म है। शास्त्री ने बताया कि यह पुस्तक उन्होंने दक्षिण राज्य में बीते छह माह पहले पांच दिन में भगवान हनुमान से मिली प्रेरणा से लिखी है। इसमें किसी की तुलना नहीं है।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कथाओं में कई युवा व परिवार मिले, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया था। ऐसे में बच्चों को धर्म की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। वह कहते हैं कि यह पुस्तक तब सार्थक होगी, जब हर बच्चे के बैग में यह होगी। इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश से की जाएगी। जिसके बाद सभी राज्यों में इससे परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी।

इसका उद्देश्य युवाओं का चरित्र संवारना है। उन्होंने बताया कि पुस्तक ऊर्दू, पंजाबी, मराठी समेत सभी भाषाओं में अनुवाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा पर रोक लगनी चाहिए। मंदिर का पुनर्निमाण कराया जा रहा है। यह अच्छा संकेत है। ज्ञानवापी में नंदी निकल आए हैं, अब भगवान शंकर निकलने तय हैं।

सनातन धर्म के मंडन का विचार होना चाहिए: डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

इस मौके पर सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संत जीवंत तीर्थ माने जाते हैं। धर्म को लेकर बच्चे पूछते हैं, लेकिन कई अभिभावकों को पता ही नहीं होता। धर्म पढ़ना तो दूर, पलटा तक नहीं है। आज अगर सनातन के खंडन का विचार है, तो मंडन का विचार भी होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री सबसे युवा सनातन धर्म के प्रचारक हैं, जोकि संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यह अमृत काल की पीढ़ी आने वाले सनातन धर्म का एक हजार वर्ष का इतिहास बनाएगी।

वहीं, परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ को बागेश्वर धाम ध्यान में लाए हैं। आस्था का सम्मान ही सनातन धर्म है। वर्तमान समय में लोग किताबों और अपने आप को भी पढ़ना भूल गए हैं। सनातन नहीं होगा, तो धर्मनिरपेक्षता, मानवता नहीं होगी। सनातन बीमारी नहीं इलाज है। राम विवाद नहीं समाधान है। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे।

जैस्मीन शाह ने कहा कि हम चाहते हैं कि युवा भारत के विकास और सार्वजनिक कल्याण को आकार दें और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के कौशलों से संपन्न करें।

AAP ने 'अंबेडकर फेलोशिप' के तहत 20 फेलोज का किया चयन, सीएम केजरीवाल बोले- ये प्रोग्राम स्वर्णिम अवसर

आम आदमी पार्टी ने कठिन चयन प्रक्रिया के बाद मिशन 2024 के लिए 20 अंबेडकर फेलोज को शामिल किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि किसी में भारतीय राजनीति को बदलने और भारत को दुनिया का नंबर-1 देश बनाने को लेकर उत्साह है तो उसके लिए यह फैलोशिप प्रोग्राम स्वर्णिम अवसर है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन के उद्देश्य से ₹अंबेडकर फेलोशिप₹ प्रोग्राम के तहत 20 फेलोज का चयन किया है। इसके लिए देश में सबसे तेजी से बढ़ती राष्ट्रीय पार्टी को देशभर से हजारों आवेदन प्राप्त हुए थे और 2 महीने के कठिन चयन प्रक्रिया के बाद 20 उम्मीदवारों को चुना गया है।

फेलोज को ट्रेनिंग के पहले दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता और वरिष्ठ नेता जैस्मीन शाह, रीना गुप्ता और नीरज पांडे ने संबोधित कर उनके दायित्वों के बारे में बताया। ये फेलोज दिल्ली और पंजाब में ₹आप₹ के फेमस मॉडल जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार, मुफ्त पानी और बिजली नीति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति आदि के पीछे के संघर्षों की वजह से आकर्षित हुए हैं।

ओरिएंटेशन के दौरान फेलोज को संबोधित करते हुए पंकज गुप्ता ने कहा कि इन फेलोज में वह लोग भी शामिल थे, जो पहले बैच में शामिल नहीं हो सके थे। इंटरव्यू के दौरान इन युवा लोगों में देश के कल्याण के लिए योगदान देने की उत्सुकता दिखाई दी। वहीं, जो लोग पहले बैच में नहीं आ सके थे, वह भी अब ₹आप₹ के विस्तृत परिवार का हिस्सा हैं।

जैस्मीन शाह ने कहा कि हम चाहते हैं कि युवा भारत के विकास और सार्वजनिक कल्याण को आकार दें और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के कौशलों से संपन्न करें। ये फेलोज प्रमुख रूप से विदेशी संस्थानों समेत प्रसिद्ध संगठन और विश्वविद्यालयों से आए हैं। इनमें ज्यादातर में राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। इस बैच में कई राज्यों

के लोग शामिल हैं, जो ₹आप₹ के विकास विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। रीना गुप्ता ने कहा कि हमारे युवा इस देश के चुनौतियों के लिए अद्वितीय समाधान रखते हैं। राजनीति एकमात्र तरीका है, जिससे हम सामाजिक परिवर्तन को व्यापक स्तर पर ला सकते हैं। आज के युवा इस बात को समझते हैं और ₹आप₹ के भारत को नंबर-1 बनाने के इरादे के लिए दृष्टिकोण रखते हैं।

इस फेलोशिप को 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल दिसंबर में घोषित किया था। इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक परिवर्तन में युवाओं को शामिल करना था। उन्होंने फेलोशिप के शुरू होने पर युवाओं से अपील की थी कि ₹आप₹ भारत के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है, क्योंकि यह ईमानदार और शिक्षित लोगों की पार्टी है। आप देश में कहीं भी रहते हैं, अगर आपके अंदर भारतीय राजनीति को बदलने और भारत को दुनिया का नंबर-1 देश बनाने की उत्साह है, तो यह फैलोशिप कार्यक्रम आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है।

इस 11 महीने के कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं को योग्यताओं से संपन्न करना है, ताकि वह अपनी आवाज बुलंद कर सकें, अपनी समस्याओं के लिए समाधान खोज सकें और चुनाव का नजदीक से अनुभव सकें। ये फेलोज पार्टी के घोषणा पत्र, संचार रणनीति और देशभर में राजनीतिक प्रचार में पार्टी नेतृत्व के साथ काम करेंगे। यह फेलोशिप प्रभावी अनुभव और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करेगी।

आम आदमी पार्टी ने फेलोज का स्वागत करते हुए कहा कि भारत का युवा एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जो उन रास्तों को निर्धारित करेगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकसित होंगे। इस महत्वपूर्ण संदर्भ में आगे आएं और अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दें, जो 1 बिलियन से अधिक भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करता है और देश के हर कोने को महत्वपूर्ण आवाज देता है।

फेलोशिप के रूप में आपको विकास और सार्वजनिक कल्याण को आकार देने और सभी नागरिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्रणा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह फेलोशिप फेलोज की विशेषताओं को बढ़ावा देगी और कटिंग-एज राजनीतिक को रिसर्च करने और प्रोजेक्ट लीड करने की क्षमता को ताकत देगी। जिससे कि वह अपने शोध और तार्किक सोच के कौशल का उपयोग करके उन मुद्दों पर प्रभावशाली प्रचार करें जो आज उनके और राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।

ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया: यूपी के इस मंडल में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फेल, क, ख, ग भी नहीं पढ़ पा रहे बच्चे

मोहिनी और फैजान कक्षा एक में पढ़ते हैं लेकिन उन्हें क से ज्ञ तक के अक्षरों का भी ज्ञान नहीं है। जब उनसे किताब में कख ग पढ़ने के लिए कहा गया तो वह शब्द भूल गए। इसके साथ ही वह उच्चारण तक नहीं कर पाए। यह हाल तब है जब भारत सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से पिछले दो सालों से निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है।

नोएडा। मोहिनी और फैजान कक्षा एक में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें क से लेकर ज्ञ तक के अक्षरों का भी ज्ञान नहीं है। जब उनसे किताब में क,ख, ग पढ़ने के लिए कहा गया तो वह शब्द भूल गए। इसके साथ ही वह उच्चारण तक नहीं कर पा रहे थे।

यह हाल तब है जब भारत सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से पिछले दो सालों से निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान शुरू करने का उद्देश्य ही यही था कि छात्रों को हिंदी के वर्ण और गणित के अंकों की पहचान हो सके, लेकिन यह अभियान लगातार फेल साबित हो रहा है।

मेरठ मंडल के स्कूल नहीं उतरे खरे

जनवरी के आखिरी सप्ताह में जारी हुई निपुण आंकलन रिपोर्ट में मेरठ मंडल के अधिकतर स्कूलों में कक्षा एक से तीन तक के छात्र तय लक्ष्य पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं।

मेरठ मंडल के जिलों में 21.66 प्रतिशत स्कूल के छात्र ही हिंदी और गणित के लक्ष्य को दो साल में प्राप्त करने में सफल साबित हुए हैं।

हर जनपद में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर निपुण भारत अभियान के तहत हर साल लाखों रुपये खर्च हो रहे है, लेकिन उसका परिणाम शून्य है।

सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान, कायाकल्प, शारदा अभियान सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं कि छात्रों को स्कूलों से जोड़ा जा सके और उन्हें भाषा और गणित में निपुण बनाया जा सके, लेकिन सभी योजनाएं कागजों पर प्रगाति कर रही हैं, लेकिन धरातल पर दम तोड़ रही है।

नंबर गेम

मंडल के 3148 में से 603 स्कूल ही मिले निपुण

मंडल के 21.66 प्रतिशत स्कूल के ही छात्र भाषा और गणित का तय कर पाए लक्ष्य

मेरठ के 13 प्रतिशत ही स्कूल के छात्र ही निपुण

बागपत के 31 प्रतिशत स्कूल हुए निपुण

मेरठ में 13 प्रतिशत स्कूल के छात्र ही निपुण

डायट प्रशिक्षुओं की ओर से प्रतिदिन दो स्कूलों के छात्रों का मूल्याकंन किया गया, जिसके लिए उन्हें 500 रुपये प्रति स्कूल मानदेय दिया गया है। नंवबर और दिसंबर में प्रदेश के सभी कक्षा एक से तीन तक के छात्रों का आंकलन निपुण लक्ष्य एप के माध्यम से कराया गया।

एप के माध्यम से कराएं गए परिणाम में गौतमबुद्ध नगर के 383 में 73, हापुड़ के 354 में 92, मेरठ के 708 में 93, गाजियाबाद के 316 में 93, बुलंदशहर के 954 में 117, बागपत के 433 में 135 स्कूल ही निपुण मिले हैं। मेरठ मंडल में सबसे खराब स्थिति मेरठ जिले की है।

जहां पूरे मंडल की निगरानी करने के लिए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बैठते है। वहीं गौतमबुद्ध नगर के 19 प्रतिशत स्कूल ही निपुण मिले है। जबकि सितंबर में जारी हुए परिणाम में जिले ने प्रदेश में टाप किया था।

एप में आई कई परेशानी

शिक्षकों ने बताया कि निपुण लक्ष्य एप में कई तकनीकी दिक्कतें आने से कई स्कूल निपुण होने के बावजूद भी बाहर हो गए। हर कक्षा में 12 छात्रों का निपुण एसेसमेंट होना था, जिसमें नौ छात्रों के निपुण होने से वह कक्षा निपुण घोषित की जा रही थी।

12 छात्रों के एसेसमेंट की सूची राज्य परियोजना कार्यालय से भेजी गई थी। सूची में कई ऐसे छात्रों का नाम था, जो स्कूल छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही एसेसमेंट के समय कई छात्र स्कूल नहीं आए।

इस वजह से स्कूल निपुण नहीं हो पाए। एक स्कूल में 36 में से 27 छात्रों को निपुण होना जरूरी था। 27 में से एक भी छात्र यदि फेल हो गया तो वह स्कूल निपुण की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

कक्षावार भाषा में निपुण होने के मानक

कक्षा-1: पांच सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेना

कक्षा-2: 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ लेना

कक्षा-3: 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेना

कक्षावार गणित में निपुण होने के मानक

कक्षा-1: एक अंकीय जोड़ व घटाव कर लेना

कक्षा-2: दो अंकीय जोड़ व घटाव कर लेना

कक्षा-3: तीन अंकीय जोड व घटाव कर लेना

डीएलएड प्रशिक्षुओं की ओर से कराए गए एसेसमेंट के परिणाम की समीक्षा की जाएगी। छात्रों को निपुण बनाने का लक्ष्य 2025-26 है। इससे पहले सभी स्कूलों के छात्रों को निपुण घोषित कर दिया जाएगा।

- दिनेश कुमार यादव, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक

कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम बोले- मैं सनातन के साथ हूं जो सत्य है

कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मेरी पहचान सनातन के सेवक के रूप में है। मैं भारत के साथ हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए निमंत्रण देने के बाद से चर्चा में हैं।

गाजियाबाद। कांग्रेस नेता और कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए निमंत्रण देने के बाद से चर्चा में हैं। पीएम ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं भारत के साथ हूं और सनातन के साथ हूं।

कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मेरी पहचान सनातन के एक सेवक के रूप में है। आगे कहा कि मैं भारत के साथ हूं और सनातन के साथ हूं। सनातन वह धर्म है जो सत्य और शाश्वत है।

श्री कल्कि धाम का शिलान्यास

जानकारी के लिए बता दें कि 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होना है। इसमें देशभर के साधु संत शामिल होंगे। इसमें शामिल होने के लिए सिर्फ साधू संतों को ही नहीं सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख को भेजे जा रहे हैं।

पीएम को दिया निमंत्रण

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र के साथ कल्कि दूत पुस्तक भी भेंट की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि ऐंचोड़ा कंबोह में विश्व का पहला मंदिर होगा जहां भगवान विष्णु के दस अवतार के गर्भगृह होंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि का अंतिम अवतार संभल में होगा।

भगवान श्री कल्कि के अवतार लेने से पहले उनका भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। बताया कि प्रधानमंत्री ने निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया है। आचार्य ने बताया कि देशभर के सभी साधू संत और राजनीतिक दलों के प्रमुखों को निमंत्रण दिए जा रहे हैं और दिए भी जा चुके हैं।

भव्य तरीके से शिलान्यास किया जाना है। उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए शिलान्यास के निमंत्रण पत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर आभार जताया है।

इन 15 नस्ल के कुत्तों के पालना पर बैन है: पिटबुल ने महिला और दो साल के बच्चे पर किया अटैक, केस दर्ज

गुरुग्राम में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्पूट रेडरेसल फोरम ने कुछ नस्ल के कुत्तों पर बैन लगा दिया था। 2022 में 15 नस्लों के कुत्तों पर बैन लगाया गया है जिसमें पिटबुल, डोगो अर्जेंटिनो, रॉट वाइलर, नेपॉलियन मस्टिफ, बुहअबुल, प्रेस कनेरियो, वूल्फ डॉग, बैनडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासिलेरियो, केन कॉर्सो आदि ब्रीड के कुत्तों को पालने पर पाबंदी है।

नई दिल्ली। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिटबुल ने महिला व बच्चे को काट लिया। इस तरह के डॉग को पालने पर गुरुग्राम में पाबंदी है। सेक्टर पांच थाना पुलिस ने शिकायत के बाद डॉग के मालिक के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार बुधवार को भीमगढ़ खेड़ी निवासी एक महिला व बच्चे को पिटबुल ने काट लिया। महिला अपने भाई के दो साल के बच्चे के साथ शाम को गेट के सामने खड़ी थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के पिटबुल ने महिला और छोटे बच्चे को काट कर घायल कर दिया। महिला के भाई ने सेक्टर-5 स्थित थाने में गुरुवार को एफआईआर दर्ज कराई। जांच अधिकारी महीपाल ने बताया कि अभी कुत्ते की नस्ल का पता नहीं चल पाया है।

एक महीने में कुत्तों के काटने के तीन से ज्यादा मामले

गुरुग्राम में पिछले एक महीने में कुत्तों के काटने के मामलों में इजाफा हुआ है। बीते 19 जनवरी को सेक्टर-23ए में एक छोटी बच्ची को एक लावारिस कुत्ते ने काट लिया। मालिबू टाउन में भी एक महिला सहायिका को कुत्ते ने काट लिया। सेक्टर-56 स्थित केंद्रीय विहार में एक कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया और एक दूसरा कुत्ता महिला का बैग उठाकर ले गया। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों को डर व्याप्त है और इस संबंध में सख्त और स्थाई कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

पिटबुल डॉग ब्रीड पालना है बैन

गुरुग्राम में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्पूट रेडरेसल फोरम ने कुछ नस्ल के कुत्तों पर बैन लगा दिया था। 2022 में 15 नस्लों के कुत्तों पर बैन लगाया गया है जिसमें पिटबुल, डोगो अर्जेंटिनो, रॉट वाइलर, नेपॉलियन मस्टिफ, बुहअबुल, प्रेस कनेरियो, वूल्फ डॉग, बैनडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासिलेरियो, केन कॉर्सो आदि ब्रीड के कुत्तों को पालने पर पाबंदी है। यह सभी खतरनाक प्रवृति के माने जाते हैं।

कुत्ते के काटने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के कुत्तों को पालने पर पाबंदी है। नगर निगम की ओर से भी इसमें राय मांगी जा रही है। -महीपाल, जांच अधिकारी।

दो महिला समेत बंद कमरे में मिले चार शव

जलती गैस की वजह से दम घुटने से मौत की आशंका

पुलिस ने कमरा तोड़कर चारों शवों को बाहर निकाला। कमरे में गैस पर किसी बड़े बर्तन में आलू रखे हुए थे जो जलकर राख हो गए थे। पुलिस का कहना है कि कमरे का साइज काफी छोटा था और गैस हवा निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गैस जली छोड़ने के कारण दम घुटने से चारों की मौत हो गई।

ग्रेटर नोएडा। वेस्ट स्थित ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र के तुस्याना गांव के गारकपुर में दो महिला और दो पुरुषों के बंद कमरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन -फानन में सूचना पर पहुंची पुलिस ने गेट तोड़कर चारों के शवों को बाहर निकाला। चारों गारकपुर में किराये का कमरा लेकर रह रहे थे।

जलती गैस से दम घुटने से मौत

पुलिस ने चारो शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि चारों की मौत जलती गैस की वजह से दम घुटने से हुई है। तुस्याना गांव के गारकपुर में पवन बिधूड़ी ने किराये के कमरे बना रखे हैं। जिसमें दो सगे भाई चंद्रेश, राजेश व उनकी बहन बबली और चंद्रेश की पत्नी निशा किराये पर रहती थी। शुक्रवार देर शाम का चारों के शव कमरे में मिले।

पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया दम घुटने से चारों की मौत हुई है। मकानमालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर चारों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि ईकोटेक-तीन थाना क्षेत्र के गांव तुस्याना निवासी पवन बिधूड़ी के मकान में हाथरस के सराय सिकंदराऊ निवासी एक परिवार के चारों लोग रहे रहे थे।

अंदर से बंद था कमरे का दरवाजा

चंद्रेश और राजेश रेहड़ी पर पराठे बेचने का काम करते थे। शुक्रवार शाम लगभग छह बजे पड़ोसी ने चारों के कमरे से दुर्गंध आने की जानकारी मकान मालिक को दी। अंदर से दरवाजा बंद होने के कारण अनहोनी की आशंका पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कमरा तोड़कर चारों शवों को बाहर निकाला।

कमरे में गैस पर किसी बड़े बर्तन में आलू रखे हुए थे, जो जलकर राख हो गए थे। पुलिस का कहना है कि कमरे का साइज काफी छोटा था और गैस हवा निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गैस जली छोड़ने के कारण दम घुटने से चारों की मौत हो गई। मकान मालिक का कहना है कि चारों लोग बृहस्पतिवार रात सोए थे, इसके बाद हादसे का शिकार हो गए।

बिजली के पोल से टकराकर आग का गोला बनी कार, एक युवक की जलकर हुई मौत

कार चालक की पहचान मोहित 32 पुत्र दिनेश राघव दौला के रूप में हुई हैं। मृतक युवक शुक्रवार देर रात्रि 11 बजे अपने घर से कार में सवार होकर सोहना की और जा रहा था दमदमा रोड गांव लोहटकी के समीप उनकी कार बिजली के पोल से टकरा गई।

नई दिल्ली। शुक्रवार देर रात सोहना दमदमा मार्ग पर बड़ा हादसा घट गया। कार सड़क के किनारे खड़े बिजली के पोल से टकरा गई कार की टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार में आग लग गई ओर कार चालक सकी मौके पर ही मौत हो गई। कार में आग लगने की घटना को देख आसपास के लोग इकट्ठे हो गए ओर चालक को कार से बाहर निकाल सोहना अस्पताल पहुंचाया। फायर बिर्गेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग बुझाई।

कार चालक की पहचान मोहित 32 पुत्र दिनेश राघव दौला के रूप में हुई हैं। मृतक युवक शुक्रवार देर रात्रि 11 बजे अपने घर से कार में सवार होकर सोहना की और जा रहा था दमदमा रोड गांव लोहटकी के समीप उनकी कार बिजली के पोल से टकरा गई, जिसमें मोहित की मौत हो गई। कार में सीएन जी लगी थी। मृतक के शव को नागरिक अस्पताल के शव दाह गृह में रखवा दिया गया।

ग्रेटर नोएडा में अतीक अहमद का मकान हुआ कुर्क, बेटे ने यहीं रहकर की थी पढ़ाई

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-36 स्थित माफिया अतीक के मकान को प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने कुर्क किया है। उमेश पाल की हत्या के बाद कई बार पुलिस इस मकान पर जांच के लिए पहुंची थी अब तक की जांच में पता चला है कि अतीक के बेटे ने इसी मकान में रहकर नोएडा में पढ़ाई की थी।

ग्रेटर नोएडा। शहर के सेक्टर-36 स्थित माफिया अतीक के मकान को प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने कुर्क किया है। उमेश पाल की हत्या के बाद कई बार पुलिस इस मकान पर जांच के लिए पहुंची थी, अब तक की जांच में पता चला है कि अतीक के बेटे ने इसी मकान में रहकर नोएडा में पढ़ाई की थी।

नीतीश कुमार ने जो चाल चली है...उसके असल परिणाम अभी आने बाकी हैं

लालू बेशक नीतीश के सहयोगी बने, लेकिन वे 1994 की दगाबाजी नहीं भूले। धीरे-धीरे शासन में लालू परिवार का दबदबा बढ़ा तो नीतीश ने 2017 में फिर बीजेपी का साथ ले लिया। इसका उन्हें 2019 के आम चुनावों में फायदा भी हुआ। उनके 16 सांसद चुने गए।

उमेश चतुर्वेदी

भारतीय गांवों का एक खेल है, दोल्हा-पाती। इसमें खिलाड़ी अपने को बचाने के लिए लगातार एक डाल से दूसरी डाल पर फांदते-कूदते रहते हैं। इस तरह वे खुद को खेल के नियम के अनुसार बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे तो यह खेल भारत के तकरीबन हर इलाके के गांवों में प्रचलित है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में यह खेल कुछ ज्यादा ही प्रचलित रहा है। शायद यही वजह है कि बिहार की नौंवी बार कमान संभाल चुके नीतीश कुमार को लेकर दोल्हा-पाती के खिलाड़ी जैसी अवधारणा बन गई है। करीब एक दशक में जिस तरह चार बार नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला, अपने साथी बदले, वह कूद-फांद का ही रूप है।

दिलचस्प है कि नैतिकता और मर्यादा की सबसे ज्यादा दुहाई राजनीति देती है, लेकिन नैतिकताओं और मर्यादाओं का भंजन सबसे ज्यादा राजनीति ही करती है। नीतीश, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, कम से कम बिहार के संदर्भ में तीनों ही इसी प्रवृत्ति के उदाहरण बनकर सामने आए हैं। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था, नीतीश कुमार ने उन्हें सांप्रदायिक करार देते हुए उस आठ साल से जिस पार्टी के साथ सत्ता चला रहे थे, उस भाजपा का दामन छोड़ दिया था। इसके पहले भी वे नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी सोच को जाहिर कर चुके थे। साल 2008 में जब कोसी नदी ने समंदर का रूप धर लिया था, तब गुजरात से बिहार पहुंची राहत की खेप को नीतीश ने बैरंग वापस करा दिया था। क्योंकि उस वक्त उनकी नजर में सांप्रदायिक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

2013 में नीतीश कुमार ने उस लालू का दामन थाम लिया, जिनके विरोध में उन्होंने 1994 में जनता दल छोड़कर जार्ज फर्नांडिस की अगुआई में समता पार्टी बनाई थी। भाजपा के साथ 1996 में समता पार्टी ने जो गठबंधन किया, उसका नतीजा ही रहा कि 2005 के बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश की अगुआई में लालू यादव की लगभग अजेय समझी जाने वाली सत्ता को उखाड़ फेंका गया। तब नीतीश ने नया इतिहास रचा, लेकिन इसमें सहयोग बीजेपी का भी रहा। नीतीश-भाजपा की सरकार ने 2006-2010 के दौरान बिहार की कार्यशैली बदली, कानून-व्यवस्था को बेहतर किया और कई कीर्तिमान रचे। इसका असर यह हुआ कि 2010 के विधानसभा चुनावों में लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी पराजय हुई। ऐसा माना जाने लगा कि लालू यादव की पार्टी अब खत्म हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने 2013 में पलटी मारी और इसके बाद 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल को जैसे जीवनदान मिल गया। लेकिन नीतीश को लालू का यह साथ ज्यादा दिन रास नहीं आया। हालांकि इस बीच बिहार के जीन को लेकर नीतीश कुमार ने ऐसा अभियान चलाया कि बोरे में भरकर बिहार के लोग अपने बाल नरेंद्र मोदी के पते पर भेजते रहे। तब बिहारी लोगों का बाल उनकी शुद्ध बिहारी जीन का प्रतीक था।

लालू बेशक नीतीश के सहयोगी बने, लेकिन वे 1994 की दगाबाजी नहीं भूले। धीरे-धीरे शासन में लालू परिवार का दबदबा बढ़ा तो नीतीश ने 2017 में फिर बीजेपी का साथ ले लिया। इसका उन्हें 2019 के आम चुनावों में फायदा भी हुआ। उनके 16 सांसद चुने गए। बीजेपी को अपनी पुराने 22 सांसदों में से कुछ के टिकट काट कर उनकी सीट जनता दल यू को देनी पड़ी। इसी गठबंधन ने 2020 का

विधानसभा चुनाव भी लड़ा। इस चुनाव में लोकजनशक्ति-रामविलास गुट के नेता चिराग ने सिर्फ जनता दल यू की सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे और 2005 के बाद पहली बार नीतीश की पार्टी को सबसे कम यानी 5 सीटें मिलीं। नीतीश ने इसे बीजेपी का खेल माना और 10 अगस्त 2022 को बीजेपी का साथ छोड़ उस आरजेडी का दामन थाम लिया, जिसके नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें पलटू चाचा की उपाधि दी थी। बिहार में 28 जनवरी

2024 को नीतीश ने फिर पाला बदल लिया और उनके लिए सारे दरवाजे बंद करने का बार-बार दावा करने वाली बीजेपी ने बदले हालात में उनके लिए दरवाजे खोल दिए। नीतीश भी अपना वह बयान भूल गए कि मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार की छवि पलटू बाबा के रूप में स्थायी हो गई।

राजनीति दरअसल समूचा शीर्ष नेतृत्व का खेल है। दिलचस्प यह है कि शीर्ष नेतृत्व सारे कदम अपने कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भावनाओं के नाम पर उठाती है। जब भी कोई गठबंधन टूटता है तो घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता पुराने साथी को दुश्मन मानकर उसके खिलाफ दुश्मनी की हद तक हमलावर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर वही दल साथ आ जाते हैं तो जमीनी स्तर पर दुश्मनी निभाने वालों के सामने खीस निपोरने और ठगा महसूस करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बिहार में भी यही हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं सूझ रहा कि वे अब उस नीतीश को कैसे पचाएं, जिन्होंने उन्हें अछूत बताया, उनके नेताओं को विधानसभा में खरी-खोटी सुनाई। विधानसभा अध्यक्ष का आसन सदन में सबसे ऊंचा होता है।

लेकिन नीतीश ने उस आसन पर बैठे विजय सिन्हा को भी नहीं छोड़ा था। सदन में महिलाओं को लेकर उन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले तकरीबन अश्लीलता की हद तक का बयान दिया था। तब भाजपा की एक विधायक फूट-फूटकर रो पड़ी थीं। बदले हालात में उनकी स्थिति का अनुमान ही लगाया जा सकता है। जनता दल यू के एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि उनका अपना कोर वोटर, जिसमें नीतीश की अपनी कुर्मी जाति के भी लोग हैं, अब गाली देने लगे हैं। उनके सामने भी नीतीश की लानत-मलामत की गई। लोगों का कहना है कि क्या बिहार के राजनीतिक दलों और नेताओं की आंखों में पानी नहीं रह गया है?

बिहार के बदले राजनीतिक गठबंधन की नई सरकार को बिहार के हित में बताया जा रहा है। इससे बीजेपी खुद को बेहतर स्थिति में पा रही है। राष्ट्रीय जनता दल खुद को ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में दो चीजें कम से कम फौरी तौर पर साफ हुई हैं। नीतीश का प्रभामंडल कमजोर हुआ है, वहीं लालू की विरासत पर चलने वाले तेजस्वी का कद बढ़ा है। सरकार टूटने के बाद तेजस्वी ने काफी परिपक्वता का परिचय दिया। इसके चलते बिहार में एक वर्ग ऐसा दिख रहा है, जिसे तेजस्वी से सहानुभूति हो रही है। इसका संकेत साफ है। अगर तेजस्वी का कोर वोटर अपनी आक्रामकता पर काबू रख पाया तो बिहार में आने वाले दिनों में दो ही राजनीतिक ध्रुव होंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी भविष्य के चुनावों छीजती चली

जाएगी। शायद यही वजह है कि भाजपा से अलगाव के बाद जनता दल यू के जिन नेताओं ने नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं की कटु आलोचनाएं की थीं, वे अब भाजपा शरणं गच्छामि की मुद्रा में आते नजर आ रहे हैं। बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण का असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा, इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिलना तय माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अभी देश में दो लहर चल रही है, मोदी लहर और राम लहर। इसका असर चुनावों पर दिखेगा। लेकिन यह भी तय है कि उसके बाद होने वाले चुनावों में जनता दल यू को नीतीश की पलटबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर है कि उसका फायदा भाजपा और आरजेडी को ही मिलेगा। कह सकते हैं कि बदले राजनीतिक समीकरणों की वजह से बिहार में नई राजनीति दिखेगी।

-उमेश चतुर्वेदी

Citroen का सेफ्टी पर पूरा फोकस, 6 एयरबैग के साथ आएंगी सभी गाड़ियां; जानिए डिटेल

Citroen गाड़ियों में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रख रही है। यही वजह है कि कंपनी के द्वारा हाल ही दिए गए एक बयान में कहा गया है कि अब सभी मॉडल्स में मानक सेफ्टी के तौर पर 6 एयरबैग दिए जाएंगे। इसके अलावा ISOFIX सीट एंकरेज और रियर सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे अन्य सुरक्षा बिट्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। वाहन निर्माता Citroen सेफ्टी मानकों को खास ध्यान में रख रही है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत में अपनी सभी गाड़ियों को मुख्य सेफ्टी फीचर्स के साथ पेश करेगी। ऐसा सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कहा गया है कि आगामी समय में सिट्रोएन अपने सभी कार मॉडलों को मानक के रूप में छह एयरबैग से लैस करेगी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

सभी मॉडल्स में मिलेंगे 6 एयरबैग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य सेफ्टी को इस कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही से शुरू कर दिया जाएगा। एक बयान में Citroen ने बताया कि वह न केवल 6 एयरबैग देगी बल्कि, ISOFIX सीट एंकरेज और रियर सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे अन्य सुरक्षा बिट्स को अपनी सभी कारों और सभी वेरिएंट में मानक के रूप में पेश करेगी।

सेफ्टी के लिए जरूरी है ये चीज

गाड़ियों में 6 एयरबैग और मानक सेफ्टी फीचर्स देने के मामले में सिट्रोएन भी अन्य कार निर्माताओं की लिस्ट में शामिल हो गया है। 6 एयरबैग प्रणाली में फ्रंट एयरबैग, साइड एयरबैग और कर्टेन एयरबैग शामिल हैं और कई रिसर्च से पता चला है कि ये दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों या यहां तक कि मृत्यु को रोकने में काफी जरूरी भूमिका निभाता है।

वहीं, भारत के दृष्टिकोण को देखते हुए ये और भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहां सड़कों की स्थिति कई बार दुर्घटना का कारण बन जाती है। यहां पेश की जाने वाली कारों में ऐसे सुरक्षा उपायों की भूमिका विशेष रूप से जरूरी है।

भारत में मौजूद हैं ये मॉडल

Citroen ने 2021 की शुरुआत में C5 Aircross SUV के साथ भारतीय बाजार में एंट्री की थी और मौजूदा समय में C3, eC3 इलेक्ट्रिक कार और C3 एयरक्रॉस SUV जैसे मॉडल भी पेश करता है।

2024 KTM RC 390 और RC 200 को वैश्विक स्तर पर किया गया अनवील, जानिए क्या है इसमें खास

KTM ने वैश्विक स्तर पर नई 2024 KTM RC रेंज का अनावरण किया है। इसमें दो नई कलर स्कीम जोड़ी गई हैं। जिनमें ऑरेंज ऑन ब्लू और ऑरेंज ऑन ब्लैक ऑप्शन हैं। ये रेंज भारत में बिक्री के लिए मौजूद है और नए कलर स्कीम में साल के अंत में लॉन्च हो सकती है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। ऑस्ट्रियाई मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM ने वैश्विक स्तर पर नई 2024 KTM RC रेंज का अनावरण किया है। इस वर्ष के लिए कंपनी के पास कई टू-व्हीलर्स के अपडेटेड वर्जन हैं। जिनमें RC 390, RC 200 और RC 125 शामिल हैं। अनवील की गई बाइक में नई कलर स्कीम पेश की गई हैं। इसके अलावा कुछ और बदलाव देखने को मिले हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

जोड़े गए हैं नए कलर

2024 KTM RC 390 में दो नई कलर स्कीम जोड़ी गई हैं। जिनमें ऑरेंज ऑन ब्लू और ऑरेंज ऑन ब्लैक ऑप्शन हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल सिग्नेचर ऑरेंज फ्रेम के साथ आती हैं। इसके बाद सबसे किफायती RC 125 है। इसमें नए काले और नारंगी और ब्लू और नारंगी रंग के पैलेट मिलते हैं। दोनों रंग विकल्प चमकदार काले पहियों और फ्रेमों और गहरे रंग की स्क्रीन के साथ तैयार किए गए हैं।

भारत में कब होगी लॉन्च ?

ध्यान देने वाली बात है कि RC रेंज में मैकेनिकल तौर पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कहा गया है कि इसी साल के अंत तक भारत में नए कलर स्कीम के साथ इन्हें लॉन्च किया जा सकता है।

इस बाइक पर काम कर रही KTM

वर्तमान समय में केटीएम नई पीढ़ी की RC 390 and 390 Adventure पर काम कर रही है। आगामी बाइक आकार में छोटी और नए फ्रेम पर आधारित होगी। इनमें जो इंजन दिया जाएगा वह शक्ति के मामले में और भी मजबूत होगा। वर्तमान में उपलब्ध 399 सीसी का इंजन 45bhp की शक्ति और 39nm का टॉर्क पैदा करता है।

कॉम्पैक्ट SUV खरीदने से पहले जानिए इसके फायदे और नुकसान, नहीं होगा कन्फ्यूजन

Compact SUV खरीदने के पीछे ग्राहकों का टशन होता है। क्योंकि इस तरह की गाड़ी देखने में आकर्षक लगती है। इनमें पूरी एसयूवी की तुलना में कुछ चीजें कम ऑफर की जाती है। लेकिन जब बात कम्फर्ट की आती है तो ये ग्राहकों के लिए बेस्ट साबित होती हैं। हम यहां कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने के कुछ बेनिफिट्स बताने वाले हैं।

नई दिल्ली। भारतीय वाहन मार्केट में समय के साथ कॉम्पैक्ट साइज में आने वाली गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों के भीतर ही ये सेगमेंट ग्राहकों के दिलों में स्थान बनाने में सफल हुआ है। ऐसे में बहुत से लोग होते हैं जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें कॉम्पैक्ट कार खरीदनी चाहिए या नहीं।

आज के इस लेख में हम आपको इसी तरह की गाड़ियों के बैनिफिट्स बताने वाले हैं और इसके कुछ नुकसान भी बताएंगे।

क्यों खरीदनी चाहिए कॉम्पैक्ट एसयूवी

कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने के पीछे ग्राहकों का टशन होता है। क्योंकि इस तरह की गाड़ी देखने में आकर्षक लगती है। इनमें पूरी एसयूवी की तुलना में कुछ चीजें कम ऑफर की जाती है। लेकिन जब बात कम्फर्ट की आती है तो ये ग्राहकों के लिए बेस्ट साबित होती हैं।

इनमें एसयूवी की तुलना में सीटिंग कैपिसिटी कम मिलती है और इनका साइज भी इसकी तुलना में छोटा होता है। इन्हें किसी भी जगह ड्राइविंग करने के लिहाज से तैयार किया जाता है। यानी एसयूवी के छोटी गलियों या रास्तों में फंसने की दिक्कत होती है। लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ ऐसा नहीं होता है।

पावर के मामले में कौन बेस्ट

अब बात पावर की करी जाए, तो इन गाड़ियों को भी मुख्यतौर पर ऑफरोडिंग या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर ड्राइव करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो फुल एसयूवी होती हैं उनमें कॉम्पैक्ट एसयूवी की तुलना में ज्यादा पावरफुल इंजन मिलता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी भी बहुत से मामलों में फुल साइज एसयूवी को टक्कर देती हैं।

कॉम्पैक्ट एसयूवी के उदाहरण

टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, किआ सेल्टॉस और हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ियां कॉम्पैक्ट एसयूवी के सही उदाहरण हैं। वहीं फुल साइज एसयूवी में टोयोटा फॉर्च्यूनर, फॉर्ड एंडेवर जैसी गाड़ियों को शामिल किया जा सकता है।

Kia EV9 Electric SUV को किया गया स्पॉट, जानिए कब होगी भारतीय बाजार में एंट्री ?

कंपनी EV9 फ्लैगशिप एसयूवी को जल्द प्रमुख गाड़ी के तौर पर लेकर आने वाली है। बता दें किआ EV9 कॉन्सेप्ट को 2023 ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था और उत्पादन संस्करण ने पिछले साल वैश्विक शुरुआत की थी। कहा जा रहा है कि आगामी इलेक्ट्रिक SUV कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूदा EV6 के ऊपर स्थित होगी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता किआ इन दिनों एक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी पर काम कर रही है। इसके बारे में पिछले साल 2023 में पुष्टि की गई थी कि EV9 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में इस गाड़ी को परीक्षण के दौरान देखा गया है। इससे संकेत मिलता है कि यह निकट भविष्य में भारतीय बाजार में एंट्री कर सकती है।

कंपनी EV9 फ्लैगशिप एसयूवी को जल्द प्रमुख गाड़ी के तौर पर लेकर आने वाली है। बता दें किआ EV9 कॉन्सेप्ट को 2023 ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था और उत्पादन संस्करण ने पिछले साल वैश्विक शुरुआत की थी।

कहा जा रहा है कि आगामी इलेक्ट्रिक SUV कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूदा EV6 के ऊपर स्थित होगी। E-GMP प्लेटफॉर्म पर आधारित EV9 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पावरट्रेन में उपलब्ध है।

लॉन्च और कीमत

उम्मीद है कि अपकमिंग एसयूवी को CBU रूट के माध्यम से भारत में बेचा जाएगा और संभावना है कि इसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास होगी। इसके लॉन्च की स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन स्पाई शॉट्स के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका लॉन्च नजदीक आ चुका है।

स्पेसिफिकेशन

वैश्विक स्तर पर इसके बेस स्पेक वेरिएंट में 76.1 kWh बैटरी पैक मिलता है, जिसमें 358 किलोमीटर की रेंज मिलती है और इसे एक्सल पर लगे 215 bhp इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। इसमें एक अन्य वेरिएंट भी मिलता है जो कि 99.8 kWh है। यह एक बार चार्ज करने पर 541 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है।

डिजाइन

स्पाई शॉट्स से इलेक्ट्रिक एसयूवी का डिजाइन पता चलता है। यह किआ के सिग्नेचर टाइगर नोज एलिमेंट के साथ जोड़ी गई एक ब्लैंक-ऑफ फ्रंट ग्रिल के साथ आती है। जो वर्टिकल एलईडी हेडलैम्प्स के एक सेट और एक मजबूत फ्रंट बम्पर से घिरा हुआ है। इसमें 21 इंच के बड़े अलॉय व्हील हैं। पीछे की ओर स्लीक हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ टेल लैंप्स पर वर्टिकल ट्रीटमेंट मिलता है।

AMT और AT के बीच कन्फ्यूजन कर लीजिये दूर, नहीं होगी समझने में कोई दिक्कत

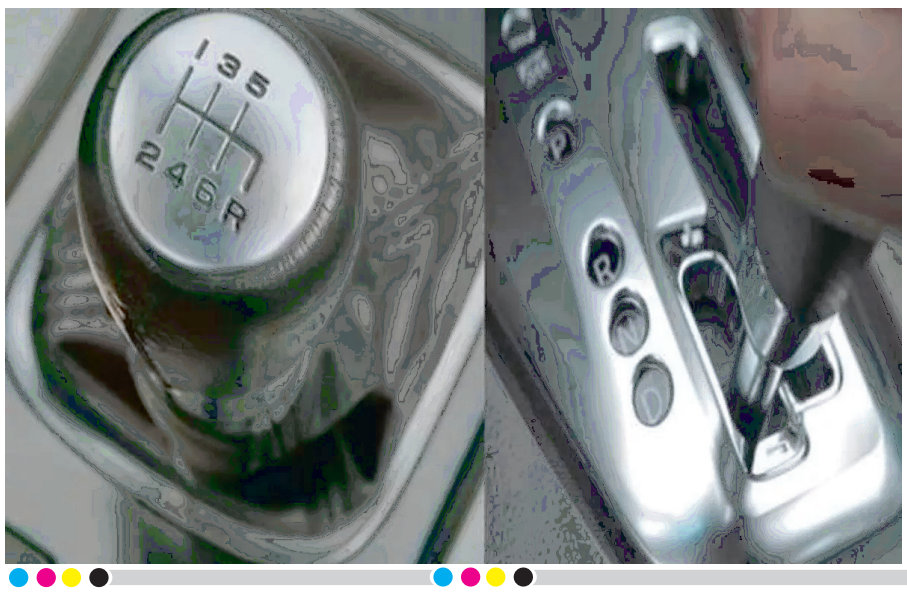

AMT vs AT गाड़ियों में कई तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम दिए जाते हैं। इनमें अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस लेख में हम आपको ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में बताने वाले हैं। AT महंगी गाड़ियों में दिया जाता है। इसमें लगे सेंसर्स स्थिति के अनुसार खुद ही गियर बदल देते हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। वर्तमान समय में आने वाली गाड़ियों में कई तरह की आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाता है। यही कारण है कि गाड़ी खरीदते वक्त हर किसी की चाहत एक अच्छे फीचर्स वाली गाड़ी खरीदने की होती है।

इस लेख में हम आपको गाड़ियों में दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सुविधा के बारे में बताने वाले हैं। जो कि ट्रांसमिशन है गाड़ियों में अनेकों तरह के ट्रांसमिशन मिलते हैं जिनको लेकर अक्सर कन्फ्यूजन होता है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं।

ट्रांसमिशन क्या होता है ?

आसान भाषा में समझें तो, ट्रांसमिशन सड़क और पहिये की सतह के बीच घर्षण की गति को संभव बनाता है। इसको गियरबॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम वाहन की जरूरतों और ड्राइविंग स्थितियों के साथ काम करने के लिए इंजन आउटपुट की गति और टॉर्क को बदलने के लिए गियर का उपयोग करके ऐसा करता है।

ट्रांसमिशन के प्रकार

मुख्य तौर पर ट्रांसमिशन दो तरह के होते हैं, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमैटिक हैं। पहले के समय में अधिकतर गाड़ियां मैनुअल ट्रांसमिशन (Manual Transmission) के साथ ही आती थीं। लेकिन अब ग्राहक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (Automatic Transmission) के साथ आने वाली गाड़ी को ज्यादा तरजीह देते हैं।

मैनुअल ट्रांसमिशन- इसमें ड्राइवर को पेडल और गियरशिफ्ट लीवर का उपयोग करके गियर शिफ्ट करने की जरूरत होती है। स्थिति के अनुसार वह अपने हिसाब से गियर बदल सकता है।

ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन- इस तरह के ट्रांसमिशन में ड्राइवर को मशक्कत नहीं करनी पड़ती है बल्कि, ये काम खुद गति और स्थिति के हिसाब से गाड़ी में लगे सेंसर्स कर रहे होते हैं।

AMT और AT में अंतर

ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)- वैसे तो इसको भी मैनुअल ट्रांसमिशन के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसमें क्लच ऑपरेशन एक खास युनिट की सहायता करता है और आप जानते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच नहीं दिया जाता है।

ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन (AT)- इस तरह के ट्रांसमिशन को टॉर्क कन्वर्टर भी कहा जाता है। इसमें कुछ भी ड्राइवर को नहीं करना होता है बल्कि गाड़ी में लगे सेंसर्स स्थिति के अनुसार सारे काम कर रहे होते हैं। यह ट्रांसमिशन महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है।

विपक्षी दलों की साख दाव पर

योगेंद्र योगी

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी ईडी और सीबीआई की निगाह है। वो गोमती रिवरफ्रंट परियोजना के अलावा खनन ठेके में कथित अनियमितताओं के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में हैं

गत वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों में जीत हासिल करने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि केंद्र की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं को बख्शेगी नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में हुई गिरफ्तारी से यह बात साबित हो गई। आश्चर्य यह है कि विपक्षी दल सोरेन की गिरफ्तारी पर भाजपा पर राजनीतिक विद्वेषता से कार्रवाई करने का आरोप तो लगा रहे हैं, किन्तु यह एक बार भी नहीं बताया कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उनके पास क्या रोडमैप है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों का शासन है, उनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके विपरीत केंद्र की भाजपा सरकार को समझ में आ गया है कि देश के मतदाता भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम के समर्थन में हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की काफी कोशिश की, किन्तु कामयाबी नहीं मिल सकी। फ्रांस से खरीदे युद्धक विमान राफेल, अडानी और अंबानी को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। इन आरोपों को लेकर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सारहीन मान कर खारिज कर दिया। इससे भाजपा का नैतिक बल बढ़ गया। भाजपा ने भ्रष्टाचार की मुहिम को तेज करने के साथ ही सोरेने जैसे नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की। विपक्ष भ्रष्टाचार पर बदले की नीयत का आरोप लगा रहा है, किन्तु प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के ज्यादातर मामलों में अदालतों से जमानत तक नहीं मिल सकी। इससे जाहिर होता है कि ईडी और सीबीआई ने ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। तृणमूल कांग्रेस और आप सहित कई पार्टियों के नेता जमानत नहीं मिलने के कारण महीनों-सालों से जेलों में बंद हैं। अदालतों ने यह माना है कि इन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं।

यही वजह है कि इनको जमानत नहीं मिल सकी, ताकि सबूतों और गवाहों को प्रभावित नहीं किया जा सके। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित 14 दलों ने ईडी और सीबीआई पर दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में जांच एजेंसियों को लेकर भविष्य के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। विपक्षी दलों का तर्क था कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ईडी की ओर से 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, जिनमें से 95 प्रतिशत विपक्षी दलों से हैं। सीबीआई की ओर से 124 जांचों में से 95 प्रतिशत से अधिक विपक्षी दलों से हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विशेष मामले के तथ्यों के बिना सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित करना संभव नहीं है। सीजेआई ने कहा कि जब आपके पास व्यक्तिगत आपराधिक मामला हो तो हमारे पास वापस आएं। मामले के तथ्यों से संबंध रखे बिना सामान्य दिशा-निर्देश देना खतरनाक होगा। इस पर विपक्षी दलों ने याचिका वापस ले ली। ज्यादातर विपक्षी दलों के नेताओं को जमानत नहीं मिलने और सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को मिली हार के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हो गए। यही वजह है कि विगत विधानसभा चुनाव और उसके बाद सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद खतरे की घंटी सबसे तेज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास ही बज रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले का सामना कर रहे हैं। इस मामले में ईडी ने केजरीवाल को चार समन भेजे हैं, लेकिन वो अभी तक केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।

केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर करीब एक दर्जन से अधिक विपक्षी नेता हैं। देर-सवेर इनका भी बच पाना मुश्किल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोप है कि रेवंत जब टीडीपी में थे, तो उन्होंने साल 2015 में विधान परिषद के चुनाव के दौरान अपने पक्ष में वोट देने के लिए एक विधायक को कथित तौर पर पचास लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी पर भी प्रवर्तन निदेशालय की नजर है। उन पर यूपीए शासन के दौरान ही कई मामले दर्ज हो गए थे। ईडी ने जगन मोहन के खिलाफ 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया था। यह मामला जगन के स्वामित्व वाली भारती सीमेंट्स के पैसों के लेने-देन के आरोप से जुड़ा है। मौजूदा समय में वामदल की सरकार सिर्फ केरल में बची है और वहां भी राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। मामला विजयन के बिजली मंत्री रहने के दौरान का है। सीबीआई ने 1995 में एसएनसी लवलिन केस में चार्जशीट दायर की थी। यह मामला इडुक्की में जलविद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कनाडाई फर्म एसएनसी लवलिन को दिए गए अनुबंध में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर कई सालों से सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की नजर है। साल 2013 से 2018 के बीच 74 करोड़ रुपए की आय को लेकर सीबीआई ने 2020 में कांग्रेस नेता पर केस दर्ज किया। केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर लालू यादव का परिवार लंबे समय से है।

बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, मीसा भारती कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा भी लालू यादव पर कई कथित भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर भी ईडी की नजर है। हुड्डा की मानेसर जमीन सौदा मामले और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की पंचकूला में भूमि आवंटन मामले की जांच चल रही है। इसी तरह राजस्थान के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सांसद कीर्ति चिदंबरम का नाम कथित एम्बुलेंस घोटाला मामले में है। कांग्रेस नेताओं पर 2015 में मामला दर्ज किया गया था, जो 2010 में फर्जी तरीके से जिकित्सा हेल्थकेयर को '08 एम्बुलेंस सर्विस' चलाने का ठेका देने से संबंधित है। कंपनी में पायलट और चिदंबरम कथित तौर पर डायरेक्टर थे। कंपनी पर अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर चालान जमा करने का आरोप है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपनी सरकार के दौरान कोयला परिवहन, शराब की दुकानों के संचालन और महादेव गेमिंग ऐप में अनियमितताओं से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के कम से कम तीन मामलों में ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी ईडी और सीबीआई की निगाह है। वो गोमती रिवरफ्रंट परियोजना के अलावा खनन ठेके में कथित अनियमितताओं के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में हैं। यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी चीफ मायावती के कार्यकाल के दौरान की कई परियोजनाओं की जांच चल रही है। हालांकि, उनका नाम एजेंसियों की किसी भी एफआईआर में नहीं है। इसके अलावा भी विपक्षी दलों के ऐसे नेताओं की सूची में कई नाम हैं, जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई में मामले दर्ज हैं।

संपादक की कलम से

'विकसित भारत' दूर की कौड़ी

अंतरिम बजट को 'विकसित भारत' की संभावनाओं का दस्तावेज मान कर विश्लेषण किए गए हैं। वर्ष 2047 अभी बहुत दूर है। अभी भारत की कुल अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। विकसित राष्ट्र के लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था का बढना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश के लोगों की जीवन-शैली, जीवन-स्तर, आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और तकनीकी सुविधाएं और सुधार और व्यापक रोजगार आदि भी बेहतर दर्जे के होने चाहिएं। फिलहाल शिक्षा पर औसतन 3.8 फीसदी और स्वास्थ्य पर मात्र 1.3 फीसदी ही खर्च किया जाता है। अर्थशास्त्री लंबे अंतराल से दलीलें देते रहे हैं कि जीडीपी का कमोबेश 6-6 फीसदी हिस्सा इन क्षेत्रों पर खर्च किया जाना चाहिए। इनके अलावा, कृषि की औसत विकास-दर मात्र 1.8 फीसदी रह गई है, जबकि कोरोना महामारी के दौर में भी यह 3 फीसदी से अधिक थी। हमारी जीडीपी में कृषि की 18-20 फीसदी भागीदारी है, लेकिन अभी एक वैश्विक रपट सामने आई है, जिसका एक निष्कर्ष यह भी है कि दुनिया की 54 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसमें किसानों की खेती वर्ष 2000 से लगातार घाटे में है। अंतरिम बजट में भी 1.27 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक की राशि कृषि मंत्रालय को आवंटित करने की घोषणा की गई है।

यह एक छिपा-दबा तथ्य है कि फसल बीमा का बजट 2.7 फीसदी, अन्नदाता संरक्षण का बजट 21 फीसदी, यूरिया सबसिडी का बजट 7.5 फीसदी घटा दिया गया है। किसान और खेती तो प्रधानमंत्री मोदी के फोकस वाले चार वर्गों में से एक हैं। विशेषज्ञ मौजूदा दौर को 'कृषि का संकट काल' मानते हैं। वित्त मंत्री बजट कम करने का कारण बता देतीं, तो हम विचार कर सकते थे। बहरहाल भारत का जो जीडीपी है और विकास-दर 7 फीसदी के आसपास रही है, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था 2030 तक दोगुनी नहीं हो सकती।

अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण हैं कि विकास-दर कमोबेश 11-12 फीसदी लगातार रहनी चाहिए। यदि गति ऐसी नहीं रहती है, तो 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने में 10 साल लग सकते हैं। फिर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के समीकरण खटाई में पड़ सकते हैं। 'विकसित भारत' का सपना मीठा और सुखद लगता है, इस पर राजनीतिक प्रचार भी खूब किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आधार वर्ष 2024 तक ऐसे हैं, जिनके मद्देनजर 'विकसित देश' का यथार्थ फिलहाल दूर की कौड़ी लगता है।

दरअसल हमारा बजट घाटे का है। यह स्थिति जुलाई के पूर्ण और आम बजट में भी रहेगी। वित्त मंत्री ने यह खुलासा भी नहीं किया कि देश पर लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है, वह कम कैसे होगा? या उसके भुगतान का अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है? बजट में कुल खर्च का अनुमान 44 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बताया गया है, जबकि राजस्व की आय 32 लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा हो सकती है। दोनों के बीच जितना फासला है, वह सालाना घाटा ही होगा। वित्त मंत्री ने वित्तीय और राजकोषीय घाटों को उल्लेख किया है। वे जीडीपी के 5 फीसदी हिस्से से भी ज्यादा हैं, जो चिंताजनक स्थिति है। बजट में 2025 तक घाटों को 4.5 फीसदी तक लाने की घोषणा की गई है। यदि ये आर्थिक असंतुलन दूर नहीं किए जाते, तो 'विकसित राष्ट्र' का सपना साकार कैसे होगा? बजट में मोटे तौर पर रोजगार और नौकरियों के विषय पर बिल्कुल सन्नाटा है। बेरोजगारों के लिए रोडमैप नहीं है।

चर्चा

केंद्रीय बजट से कितनी खुराक

चुनाव की रखवाली में आए केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में यूं तो आत्म श£ाघा के कई दरवाजे खुले हैं, लेकिन चेतावनियों के बीच राज्यों के लिए अपना आर्थिक सम्मान हासिल करना कठिन है। खास तौर पर हिमाचल जैसे राज्यों के लिए आफत का यह कठिन दौर न तो केंद्रीय बजट को सूंघ पा रहा है और न ही इसके भीतर खुद को ढांप पा रहा है। ऐसे में सुक्खू सरकार की आर्थिक कसौटियों में प्रदेश के आगामी बजट सत्र का हर कदम परीक्षाओं से भरा है। करीब दो हफ्ते बाद हिमाचल अपने बजट के माध्यम से नए कर्ज को पुकार रहा होगा, तो कहीं केंद्रीय योजनाओं के बीच खुद को निहार रहा होगा। हालांकि सुक्खू सरकार की कुछ प्राथमिकताएं केंद्रीय बजट में संबोधित हुई हैं और इनके सदके सरकार अपने प्रथम वर्ष के आर्थिक हिसाब को दूसरे से मिलाकर नए शब्दों में अभिव्यक्त करना चाहेगी। कोई नहीं जानता कि इस बार देश के आर्थिक सर्वेक्षण का ऊंट किस करवट बैठा है, लेकिन हिमाचल को अपनी हैसियत की कडियों में क्षेत्रवार ब्यौरे में इसे सिद्ध करना होगा। केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए जिस परिवहन को दौड़ाया है, कमोबेश उसी की परिपाटी में सुक्खू सरकार के बजटीय सुर, ग्रीन एनर्जी के गीत सुना रहे हैं। प्रथम वर्ष में ही युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ का प्रावधान करके सुक्खू सरकार चल रही है। ई-टैक्सी और ई-बसों की खरीद पर पचास फीसदी सब्सिडी की घोषणा ने करीब ढाई हजार युवाओं को आकर्षित किया है। सुक्खू सरकार आगे चलकर पेट्रोल-डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक टैक्सियों के संचालन को अनुमति देना चाहती है। ऐसे में राष्ट्रीय-अभियान से हिमाचल अपने हिस्से की संभावना को भी पूरा कर दे, तो आत्मनिर्भरता के खाकों में कुछ तो नूर आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट वैकल्पिक ऊर्जा के रास्ते से नागरिकों को छत के माध्यम से सौर ऊर्जा पैदा करने का आह्वान कर रहा है। यहां भी हिमाचल ने इस प्रकार की योजनाओं की व्याख्या से सौर ऊर्जा के उत्पादन को सुनिश्चित किया और आगे चलकर यह रास्ता भी खुशामदीद कह सकता है। डेयरी उत्पादन में केंद्र की योजनाओं के अवतरित करने की कोशिश में हिमाचल ने पहले ही गारंटियों की मुद्रा धारण की है। बात सिर्फ गोबर खरीद की नहीं, बल्कि दूध खरीद में प्रति किलो छह रुपए बढ़ा कर राज्य सरकार इस क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है, जबकि ढगवार में करीब डेढ़ सौ करोड़ की राशि से एक अति आधुनिक संयंत्र लगा कर खरीद और विपणन की श्रृंखला को विभिन्न दुग्ध उत्पादों के जरिए सशक्त करने के प्रयास में है। हिमाचल ने मोदी सरकार के बजट को विकास के हर पहलू, वित्तीय प्रोत्साहन के हर बिंदु, विषयों के हर अवसर और संभावनाओं के हर अक्स में सुना होगा, लेकिन पर्यटन और कनेक्टिविटी की दृष्टि के हर उल्लेख से पर्वतीय प्रदेश को अपनी वर्जनाएं तोडने का एहसास करने का अवसर मिलना चाहिए। केंद्र अपनी उड़ान योजना के तहत भारतीय विमानन क्षेत्र में जो उपलब्धियां अर्जित करना चाहता है, उनके ठीक सामने सुक्खू सरकार हर जिला मुख्यालय व प्रमुख शहरों में हेलिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को पहले ही आयाम तक पहुंचा चुकी है। सरकार ने चार हेलिपोर्ट को 13 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है, जबकि अन्य की प्रक्रिया जारी है। देश की तीन कंपनियों ने कुछ हेलिपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी जोड़ते हुए सेवाएं शुरू करने में रुचि दिखाई है।

रमेश धवाला, पूर्व मंत्री

पहाड़ी राज्य पर कर्ज का बढ़ता बोझ

अपनी राजनीति को चमकाने के लिए रैलियों, बिना मतलब की होर्डिंग्स, वीआईपी कल्चर, फ्री की रेवड़ियां बेचने की राजनीति को खत्म करके प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। सरकार को रेवेन्यू एकत्रित करने की कोशिश भी करनी चाहिए'

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा पहाड़ी राज्य जिसके पास आय के बहुत कम साधन हैं, देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले पहले पांच राज्यों में शामिल है। हिमाचल प्रदेश पर इन दिनों वित्तीय संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार धन की कमी की बात कही जा रही है। हालात यहां तक आ गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए सडक़ों पर उतरना पड़ रहा है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल पर अब तक 71 हजार 082 करोड़ रुपए का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न एजेंसियों से वर्ष 2020-21 में 7 हजार 295 करोड़ का कर्ज लिया। इसके अलावा 2021-22 में 5 हजार 500 करोड़ और 2023-24 में 10 हजार 294 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। कुल मिलाकर पिछले तीन साल में 23 हजार 185 करोड़ के कर्ज का बोझ प्रदेश पर लाद दिया गया है। सरकारों के आर्थिक कुप्रबंध का आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश का हर एक नागरिक लगभग एक लाख तीन हजार रुपए के बोझ में दबा हुआ है। अभी हाल में मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।

अगर ये आरोप सही हैं तो वर्तमान सरकार ने किस आधार पर विधानसभा चुनावों में लोकलुभावन और फ्री की रेवडियां बांटने के वादे किए। लेकिन इन सब आरोपों को परे रख कर देखें तो हम पाएंगे कि यह सवाल सत्ता और विपक्ष के बीच किसी एक की गलती का नहीं, बल्कि यह है कि प्रदेश ने आर्थिक सुधारों के नाम पर केवल वित्तीय कुप्रबंधन के सबूत एकत्रित किए। अपनी ही जीडीपी के द्वंद्व में लाइलाज व्यवस्था का उपचार अगर कर्ज की सीमा बढ़ाकर पूरा होगा, तो प्रदेश को अंधा और बहरा होना पड़ेगा, क्योंकि शगूफे तो हर राजनीतिक मंच के नीचे छिप कर वार कर रहे हैं। जीडीपी के साथ कर्ज का अनुशासन अगर अतीत में तीन फीसदी था, तो अब हिमाचल का राजकोषीय उत्तरदायित्व जिस विधेयक की परिक्रमा कर रहा है, उसके तहत अब पांच फीसदी की सीमा में प्रवेश हो रहा है, यानी कर्ज की रफ्तार बढ़ जाएगी। कर्जदार होने की शोभा में हम कितना जी सकते हैं, इसका हिसाब बजटीय घाटों में देखा जा सकता है। वर्तमान बजट के 50192 करोड़ के प्रस्तावों में राजस्व घाटे के 1462.94 करोड़ व वित्तीय घाटे के 7789.12 करोड़ जोड़ दिए जाएं तो 9252.06 करोड़ रुपए की जरूरत में बही खातों की खाना खराबी का क्या करेंगे। पिछले दो सालों में राज्य ने 8821.85 करोड़ का ऋण उठाकर जो तस्वीर पेश की है, उसमें आइंदा कुछ और गुल खिलेंगे। आश्चर्य यह कि पुराना कर्ज उतारने के लिए ही पिछले दो सालों में 5152.11 करोड़ उधार लेना पड़ा। आश्चर्य यह कि अब तक करीब 58000 करोड़ का ऋण उठा चुका हिमाचल बेशर्मी से हाथ फैला रहा है। यह विधेयक दरअसल हाथ फैलाने की कानूनी मन्नत है, जो रसीद बनकर भविष्य पर चस्पां है।

न चिंता कानून की छूट में है और न ही विपक्ष के वाकआउट से प्रदेश की फकीरी दूर होगी। यह हम कब स्वीकार करेंगे कि ऐसे हर प्रस्ताव या कानून से हिमाचल फकीर हो रहा है। हमारी वित्तीय व्यवस्था की कमजोरियों में यह गुण-दोष अब बचा ही नहीं कि भाजपा को कोसें या यह उम्मीद करें कि, कांग्रेस की सत्ता इसे दूर करेगी। वास्तविकता यह है कि वक्त का हर लम्हा कसूरवार बन रहा है और हम राजनीतिक तौर पर मंत्रमुग्ध होकर यह देख रहे हैं कि प्रदेश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। जिस प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन के लिए भी कर्ज उठाना पड़ता हो, वहां के आर्थिक सर्वेक्षण का मजमून भी अविश्वसनीय सा लगता है। यह इसलिए कि बोर्ड-निगमों की तश्तरी में सजी राज्य की जीडीपी घाटे में है। राज्य को पर्यटन, ऊर्जा व फल राज्य का दर्जा हासिल है, लेकिन इनसे जुड़े बोर्ड व निगम घाटे में हैं। जिस डबल इंजन सरकार के भरोसे हिमाचल केंद्र की मोदी सरकार को अपना पालना मान रहा है, उसकी विनिवेश नीति से सीखना होगा। केंद्र सरकार अपने बजट की रिक्तता में कई सरकारी उपक्रमों की बिक्री से ढाई लाख करोड़ बटोरना चाहती है, तो हिमाचल को भी अपने घाटे के बोर्ड-निगमों से इतिश्री करनी चाहिए। खर्चों में तमाम कटौतियों की जिरह जब तक सिर चढ़ कर नहीं बोलेगी, सरकारों के काफिलों में नोट उड़ते रहेंगे। अपव्यय के चक्रव्यूह में सरकार की शान-ए-शौकत के नगाड़े अगर यूं ही बजते रहेंगे, तो नई कर सीमा भी बेकार की कसरत ही साबित होगी। ऐसे में विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच एक ऐसा सहमति ज्ञापन तैयार होना चाहिए जिससे वित्तीय अनुशासन की परिपाटी बन सके। हैरानी तो यह है कि नित नए कार्यालय, कार्यालयों के स्तर का उन्नयन तथा अलाभकारी खर्चों में बढ़ोतरी के बावजूद किसी ने यह नहीं सोचा कि फिजूलखर्ची रुकनी चाहिए। हर नेता राज्य के बजट को अपना बिछौना मानकर इस्तेमाल कर रहा है और इस पर तुर्रा यह है कि सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच एक-दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। नौवें वित्तायोग पर आज भी आरोप थोपकर, हिमाचल को यह इजाजत नहीं मिलती कि निरंतर कर्ज की टोकरी उठाकर प्रदेश आगे बढ़ सकता है।

सत्ता के लाभकारी पदों का उपभोग, सरकारी कार्य संस्कृति का अवमूल्यन और पारदर्शिता व जवाबदेही के अभाव में बढ़ते कर्ज की सिसकियां कौन सुनेगा। मानसून सत्र में मुख्यमंत्री का एक बयान काफी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान हालात को देखते हुए हिमाचल की हालत श्रीलंका की तरह हो सकती है। अब समय है कि सरकारें हिमाचल की वित्तीय हालत को देखते हुए अपने फिजूल के खर्चे कम करें। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए रैलियों, बिना मतलब की होर्डिंग्स, वीआईपी कल्चर, फ्री की रेवडियां बेचने की राजनीति को खत्म करके प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करें। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को हमेशा केंद्र में मोदी सरकार को कोसने के बजाय प्रदेश में रेवन्यू एकत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हिमाचल के पहाड़ जैसे कर्ज को भविष्य में कुछ सीमा तक कम किया जा सके।

मेरे भी कुछ उसूल हैं भाई!

देखो भाई, सीधी सी बात है और बात यह है कि मेरे भी चंद उसूल हैं। मैं उधार की दारू तो पी सकता हूं। कर्ज लेकर घी भी पी सकता हूं और आड़े वक्त में किसी गधे को चरण वंदना भी कर सकता हूं। लेकिन जहां तक उसूलों की बात है, मैं इस बारे कोई समझौता नहीं करता! मैं उसूलों पर उसी तरह अडिग रहता हूं, जिस तरह मुल्क की हुकूमत के सामने महंगाई और भ्रष्टाचार अडिग रहता है। उसूलों का तो मैं इतना पक्का हूं भाई कि वक्त पडने पर अपने यारों दोस्तों को तो मझधार में छोड़ सकता हूं। नैतिकता को तिलांजलि भी दे सकता हूं। ईमानदारी की चादर को जमीन पर बिछाकर उस पर सौ जूते भी मार सकता हूं। जिस थाली में खाया, उसमें छेद भी कर सकता हूं। लेकिन अपने उसूलों की भद्द पिटते नहीं देख सकता। अपने उसूल मुझे उसी तरह प्रिय हैं, जैसे माननीयों को कुर्सी प्रिय होती है और आदरणीयों को ऊपरी कमाई प्रिय होती है। मैं मूंछ कटा सकता हूं। नाक कटवा सकता हूं। पत्नी को तिलांजलि दे सकता हूं, लेकिन उसूल नहीं छोड़ सकता। यमराज दोनों हाथ जोडक़र कहे तो भी नहीं। भले ही मुझे दुनिया क्यों न छोडनी पड़ जाए। स्वर्ग या नरक जहां भी जाऊंगा, अपने उसूल भी साथ लेकर जाऊंगा। यह जोखिम बिल्कुल नहीं लूंगा कि पीछे से कोई मेरे उसूलों से छेड़छाड़ करे। मैं देश की संस्कृति और संवैधानिक परंपराओं से छेड़छाड़ तो बर्दाश्त कर सकता हूं। बस में किसी महिला से हो रही छेड़छाड़ भी बर्दाश्त कर सकता हूं (छेड़छाड़ रोकना बस के ड्राइवर और कंडक्टर का काम होता है), लेकिन उसूलों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा सबसे पहला उसूल तो यह है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उठकर पत्नी को 'गुड मॉर्निंग' कह कर 'मॉर्निंग टी' ऑफर करता हूं या ताली बजाकर योग करता हूं या प्रभु को स्मरण करता हूं। मैं तो भाई आंख मूंदकर यह 'ध्यान' लगाता हूं कि किस विरोधी की डिबरी कैसे टाइट करनी है और किस को कैसे पटा कर अपना उल्लू सीधा करना है। यही उसूल मेरी कामयाबी का राज भी है। दूसरा उसूल है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने बिना कोई काम नहीं करता। अंतरात्मा अगर मुझे घूस लेकर किसी की फाइल क्लियर करने को कहती है, तो मैं वैसा ही करता हूं। फाइल चाहे किसी निकट संबंधी की ही क्यों न हो। वरना मुझे कौन उसूलवादी कहेगा। (घूस मैं अप्रत्यक्ष रूप से लेता हूं। प्रत्यक्ष घूस लेना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और मैं भ्रष्टाचार को उसी तरह नापसंद करता हूं, जैसे मेरी पत्नी मेरे खर्राटों को नापसंद करती है।) तीसरा उसूल यह है कि मैं फोकट में किसी की मदद नहीं करता। पहले अपने हित और स्वार्थ देखता हूं। नफा नुकसान तोलता हूं। फिर मु_ी खोलता हूं। भाई मेरे, अगर मैं यूं ही आंख मूंद कर दूसरों की मदद करता रहूं तो फिर कौन मेरे उसूलों को पूछेगा? चौथा उसूल यह है कि मैं किसी भी महत्वपूर्ण आदमी से जब भी फोन पर बात करता हूं तो पूरी बातचीत को खुद ही टेप कर लेता हूं। इस दुनिया में भगवान ने मेरे जैसे अच्छे और संभ्रांत जनों के साथ साथ काफी लुच्चे और टुच्चे टाइप के आदमी भी भेज रखे हैं। क्या पता कब कोई ऐसा व्यक्ति मुझे किसी आफत में डाल दे। तब यही उसूल मेरी वैतरणी पार लगाएगा न ! उसूल नंबर पांच यह है कि गिरगिट और प्रकृति की तरह मैं परिवर्तन में यकीन रखता हूं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम जो ठहरा। इस नियम को अपनाते हुए मैं अपने खेमें बदलता रहता हूं। कभी इस खेमे में तो कभी उस खेमे में। मूड बनने पर किसी तीसरे या चौथे खेमे में भी चला जाता हूं। अगर मुझसे कोई कतराने लगता है तो मैं अपना अलग खेमा बना लेता हूं। उसूल नंबर छह यह है कि मेरी अपनी डफली अपना राग होता है और दोनों की तान विशुद्ध रूप से मौलिक होती है। लोगों को दूर से ही पता चल जाता है कि कौन से डफली बज रही है और कौनसा राग अलापा जा रहा है। मैं किसी को दुविधा में पडने का नहीं देता। फिलहाल तो नाचीज के इतने ही उसूल हैं जी और मेरे हर उसूल की पूरे इलाके में धाक है भाई ! **गुरमीत बेदी**

जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश

अगले दो साल में 10 करोड़ तक जा सकता है आईटीआर का आंकड़ा

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत करदाताओं को आयकर में और छूट की उम्मीद पर मल्होत्रा ने बताया कि अभी पिछले साल ही इस व्यवस्था के तहत टैक्स छूट का एलान किया गया था। अभी इसका एक वर्ष ही हुआ है। कर स्थायित्व के लिए कुछ समय तक इसके प्रभाव को देखना पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी का मासिक संग्रह 1.85 लाख करोड़ को पार कर सकता है।

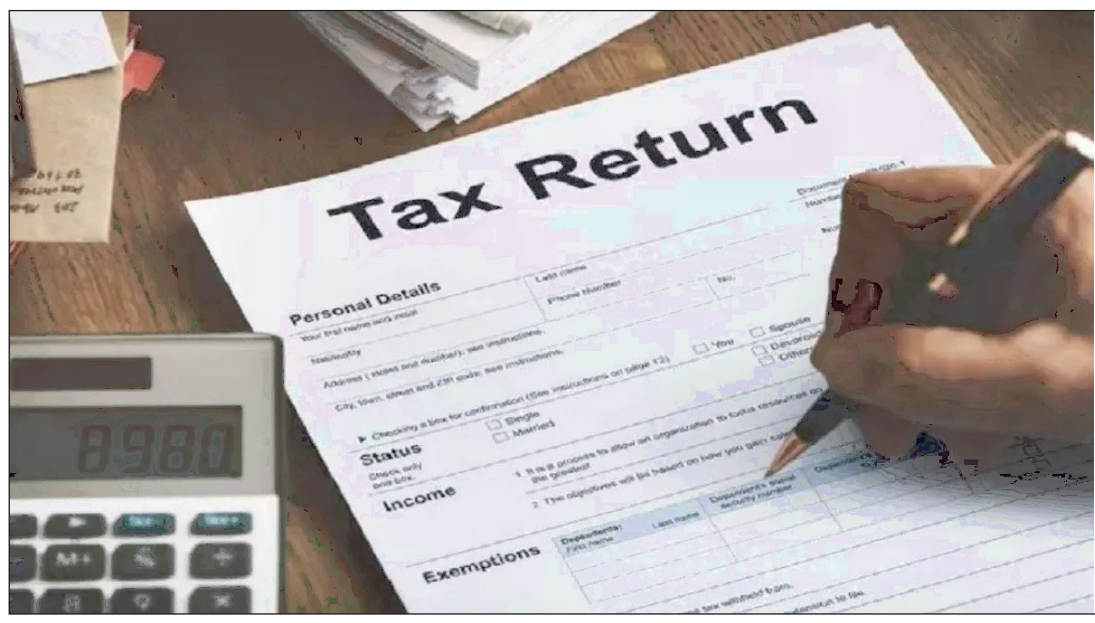

कुछ जायज तो कुछ नाजायज कारणों से यह मिलान नहीं हो पा रहा है। हम इसको रोकेंगे। अभी कई वस्तुएं जीएसटी के दायरे में नहीं है, हम उसे भी लाने का प्रयास करेंगे। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी का औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ है जो अगले वित्त वर्ष में 1.85 लाख करोड़ को पार कर सकता है।

नई दिल्ली। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की बढ़ोतरी में पूरी गुंजाइश है और सरकार टेक्नोलाजी का इस्तेमाल कर इस दिशा में आगे बढ़ रही है। उनका मानना है कि आगामी दो वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) भरने वालों की संख्या 10 करोड़ के स्तर को छू सकती है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में आइटीआर भरने वालों की संख्या आठ करोड़ के आंकड़ों को पार कर चुकी है।

प्रत्यक्ष कर में 13 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान

उन्होंने बताया कि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष कर में 13 प्रतिशत तो अप्रत्यक्ष कर में 12.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है और इस हिसाब से टैक्स के कुल संग्रह में अगले वित्त वर्ष में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी रहेगी। दैनिक जागरण को दिए साक्षात्कार में मल्होत्रा ने बताया कि अभी यह देखा जा रहा है कि वस्तु की बिक्री व वस्तु की खरीदारी में मेल नहीं है। जितनी वस्तु की बिक्री दिखाई जा रही है, उतनी खरीदारी नहीं दिखाई जा रही है।

वित्त वर्ष में 1.85 लाख करोड़ आंकड़ा

कुछ जायज तो कुछ नाजायज कारणों से यह मिलान नहीं हो पा रहा है। हम इसको रोकेंगे। अभी कई वस्तुएं जीएसटी के दायरे में नहीं है, हम उसे भी लाने का प्रयास करेंगे। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी का औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ है जो अगले वित्त वर्ष में 1.85 लाख करोड़ को पार कर सकता है।

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत करदाताओं को आयकर में और छूट की उम्मीद पर मल्होत्रा ने बताया कि अभी पिछले साल ही इस व्यवस्था के तहत टैक्स छूट का एलान किया गया था। अभी इसका एक वर्ष ही हुआ है। कर स्थायित्व के लिए कुछ समय तक इसके प्रभाव को देखना पड़ेगा।

पूर्ण बजट में आयात शुल्क में किए जा सकते हैं बदलाव

बजट में मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े कई आइटम के आयात शुल्क में कटौती की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर राजस्व सचिव ने कहा कि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में वस्तुओं के आयात शुल्क में जरूरत के मुताबिक बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बजट से ठीक एक दिन पहले ही हमने मोबाइल फोन के पार्ट्स के आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की थी।

नहीं है या भूल गए UAN Number, घबराएं नहीं इन आसान तरीकों से तुरंत करें पता

पीएफ बैलेंस (PF Balance) चेक करने के लिए यूएएन नंबर (UAN) जरूरी होता है। ऐसे में कई बार हमारे पास यूएएन नंबर नहीं होता है या हम भूल जाते हैं। अगर आपको भी अपना पीएफ बैलेंस चेक करना है और आपके पास यूएएन नंबर नहीं है तो आज हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से यूएएन नंबर ले सकते हैं।

नई दिल्ली। जिन लोगों की सैलरी से हर महीने एक फिक्सड अमाउंट पीएफ फंड (PF Fund) के लिए काटा जाता है उन्हें यूएएन (Universal Account Number) के बारे में पता होगा।

दरअसल, यूएएन एक तरह का यूनिक नंबर होता है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा एक्टिव किया जाता है। 12 डिजिट का यूएएन नंबर काफी जरूरी होता है।

इसके जरिये आसानी से पीएफ बैलेंस (PF Balance) चेक किया जा सकता है। कई बार लोग यह नंबर भूल जाते हैं या फिर कंपनी से नहीं ले पाते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से अपना यूएएन नंबर पता कर सकते हैं।

ऐसे पता करें यूएएन नंबर

आपको सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना है।

अब आप सर्विस (Services) सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा। यहां आपको Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) को सेलेक्ट करना है।

अब आप Know your UAN पर क्लिक करें। इसके बाद फिर से एक विंडो ओपन होगा। यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइन नंबर और कैप्चा भरें।

इसके बाद आपके पास ओटीपी (OTP) आएगा, उसे दर्ज करें।

अब न्यू विंडो में आपको कुछ डिटेल्स (जैसे- नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर) भरना होगा। इसके बाद Show my UAN पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर यूएएन नंबर शो होगा।

मैसेज से करें पता

आप मैसेज के जरिये भी यूएएन नंबर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको EPFOHO UAN नंबर लिखकर 7738299899 पर पंजीकृत मोबाइल नंबर से मैसेज भेजना होगा। मैसेज भेजने के बाद रिप्लाई में आपका UAN नंबर आ जाएगा।

मिस्ड कॉल से जानें UAN

आप मिस्ड कॉल से यूएएन नंबर जानने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 01122901406 पर मिस्ड कॉल देना होगा। इसके बाद आपको फोन में मैसेज आएगा।

विदेशी मुद्रा भंडार में हुई 591 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी, 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचा आंकडा

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 591 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ोतरी हुई है जिसके बाद ये बढ़कर 616.733 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जबकि पिछले हफ्ते RBI ने बताया था कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई थी। वहीं सोने का भंडार 269 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 47.481 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि 26 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 591 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 616.733 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

वहीं पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, कुल भंडार 2.795 बिलियन अमेरिकी डॉलर गिरकर 616.143 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। अक्टूबर 2021 में देश की विदेशी मुद्रा निधि 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। पिछले साल से वैश्विक विकास के कारण दबाव के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपये की रक्षा के लिए निधि को तैनात किया था, जिससे भंडार प्रभावित हुआ।

विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी

आंकड़ों में कहा गया है कि 26 जनवरी को समाप्त सप्ताह के लिए, विदेशी मुद्रा संपत्ति, भंडार का एक प्रमुख घटक, 289 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 546.144 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

डॉलर के संदर्भ में व्यक्त, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों की सराहना या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है।

सोने का भंडार में बढ़ोतरी

आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 269 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 47.481 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

शीर्ष बैंक ने कहा कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18.248 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए।

आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 4.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

रूपे क्रेडिट कार्ड का करते हैं इस्तेमाल तो जान लें इसके फायदे और नुकसान

परिवहन विशेष न्यूज

अगर आप रूपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपनी पेमेंट और ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि रूपे क्रडिट कार्ड के साथ आपको क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप स्मार्टली अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। बीते कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। भले ही हमें इसे इस्तेमाल करना आसान लगता होता है। मगर जितना ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खर्च करते हैं, उतना ही अधिक आप कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें।

इस स्थिति में रुपे क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट तरीके से उपयोग करना आपको कई लाभ दे सकता है। आपको बता दें कि RuPay क्रेडिट कार्ड नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा पेश किए गए था। बैंक एनपीसीआई के साथ साझेदारी में रुपे डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं।

RuPay क्रेडिट कार्ड के फायदे

RuPay क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन शुल्क वीजा और मास्टर कार्ड के मुकाबले कम होता है। इसका कारण ये है कि बैंक विदेशी क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए ट्रांजैक्शन शुल्क डॉलर में तय करते हैं। वहीं RuPay के स्वदेशी कार्ड होने के कारण इसपर शुल्क रुपये में लगता है।

NPCI ने इस कार्ड को सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी मजबूत बनाया है, ताकि कस्टमर्स को धोखाधड़ी और स्कैम से सुरक्षा मिल सकें।

RuPay कार्ड की मदद से पेमेंट या ट्रांजैक्शन करने पर ये काफी तेज और स्मूथ होता है। इसका कारण ये है कि इसके सर्वर भारत में स्थित हैं।

रुपे कार्ड का इस्तेमाल करके अलग अलग यूपीआई ऐप्स की मदद से पेमेंट करना बहुत आसान है, क्योंकि आप आराम से इसे अपने UPI लिंक कर सकते हैं।

RuPay कार्ड पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी काफी कम लगता है, इसके साथ ही इसकी ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये से भी कम है।

RuPay क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल आप रेस्तरां, बिजनेस, होटलों पर भी आसानी से तक सकते हैं।

RuPay क्रेडिट कार्ड की सीमाएं

विदेशों में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम ही किया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल रुपे क्रेडिट कार्ड की विदेशों में POM पर सीमित स्वीकृति है। मगर रिजर्व बैंक भारत के बाहर इस क्रेडिट कार्ड की स्वीकार्यता का दायरा बढ़ाने के लिए RuPay प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का लॉन्च करने का विचार कर रही है।

RuPay कार्ड में आपको वीजा या मास्टरकार्ड की तुलना में कम क्रेडिट लीमिट मिलती हैं। ऐसे में बड़ी खरीदारी में ये बाधा ला सकता है।

अलग-अलग बैंक की रुपे कार्ड की लीमिट अलग-अलग है, ऐसे में आपको बेस्ट ऑप्शन खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है।

घर से निकलने से पहले जांच लें पेट्रोल-डीजल के दाम, आपके शहर में इतनी है कीमत

Petrol Diesel latest Price

कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल-डीजल की कीमत तय होती है। रोज सुबह 6 बजे इनकी कीमतों को रिवाइज किया जाता है। देश के हर बड़े और छोटे शहरों के लिए आज देश की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। आइये जानते है कि आपके शहर में पेट्रोल डीजल के क्या दाम है।

नई दिल्ली। नए साल का दूसरा महिना शुरू हो गया है। हर रोज की आज भी सुबह पेट्रोल-डीजल की कीमत अपडेट हो गई है। आपको बता दें कि रोज सुबह 6 बजे यह कीमतें अपडेट हो जाती है।

जैसा ही हम जानते हैं कि पेट्रोल-डीजल की कीमत क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर तय होती है। देश की सरकारी तेल कंपनियों यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनकी कीमतों पर टैक्स, वैट, कमीशन आदि लगाते हैं।

आइये जानते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल- डीजल की कीमतें क्या है।

मेट्रोसिटी में पेट्रोल-डीजल के दाम

राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है।

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106.03 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.76 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.24 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

नोएडा समेत अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट्स

नोएडाः पेट्रोल 96.79 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्रामः पेट्रोल 97.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.05 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरुः पेट्रोल 101.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ः पेट्रोल 96.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर

हैदराबादः पेट्रोल 109.66 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर

जयपुरः पेट्रोल 108.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर

पटनाः पेट्रोल 107.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर

लखनऊः पेट्रोल 96.58 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.77 रुपये प्रति लीटर

अगले 12 महीनों में अमेजन के 50 मिलियन शेयर बेचेंगे जेफ बेजोस

जेफ बेजोस अगले साल कम से कम 50 मिलियन कंपनी शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। बिक्री कुछ शर्तों के अधीन अगले वर्ष 25 जनवरी को समाप्त होने वाली अवधि में होगी। बेजोस हाल ही में 60 वर्ष के हो गए हैं और वे अमेजन स्टॉक के लगभग एक अरब शेयरों के मालिक हैं। अमेजन वेब सर्विसेज सेगमेंट की बिक्री साल-दर-साल 13 प्रतिशत बढ़कर 24.2 बिलियन डॉलर हो गई।

31 दिसंबर, 2023 दूसरी तिमाही में अमेजन की शुद्ध बिक्री 14 प्रतिशत बढ़कर 170 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि 2022 की चौथी तिमाही में यह 149.2 बिलियन डॉलर थी। 2023 की चौथी तिमाही में शुद्ध आय बढ़कर 10.6 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि 2022 की चौथी तिमाही में यह 0.3 बिलियन डॉलर थी।

नई दिल्ली। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अगले साल कम से कम 50 मिलियन कंपनी शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अपनी फाइलिंग (एसईसी) में कहा कि इसके अरबपति संस्थापक के पास अधिकतम 50 मिलियन शेयर बेचने की ट्रेडिंग योजना थी।

फॉक्स बिजनेस की रिपोर्ट में पता चला है कि बिक्री कुछ शर्तों के अधीन अगले वर्ष 25 जनवरी को समाप्त होने वाली अवधि में होगी। बेजोस हाल ही में 60 वर्ष के हो गए हैं और वे अमेजन स्टॉक के लगभग एक अरब शेयरों के मालिक हैं।

बेजोस के शेयर है सबसे अधिक

एसईसी फाइलिंग के अनुसार, अमेजन के सात अन्य टॉप सूत्रों ने अमेजन शेयरों को बेचने के लिए ट्रेडिंग योजनाएं बनाईं। हालांकि, बेजोस के शेयरों में सबसे बड़ी मात्रा शामिल थी। अमेजन शेयरों में बेजोस की हिस्सेदारी उनकी 193.3 बिलियन डॉलर की निजी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा है।

31 दिसंबर, 2023 दूसरी तिमाही में अमेजन की शुद्ध बिक्री 14 प्रतिशत बढ़कर 170 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि 2022 की चौथी तिमाही में यह 149.2 बिलियन डॉलर थी। 2023 की चौथी तिमाही में शुद्ध आय बढ़कर 10.6 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि 2022 की चौथी तिमाही में यह 0.3 बिलियन डॉलर थी।

साल-दर-साल 13 प्रतिशत बढ़ रहा है प्रॉफिट

अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) सेगमेंट की बिक्री साल-दर-साल 13 प्रतिशत बढ़कर 24.2 बिलियन डॉलर हो गई। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने कहा कि पिछला छुट्टियों का मौसम रिकॉर्ड तोड़ने वाला था।

जेसी ने कहा कि यह Q4 एक रिकॉर्ड-ब्रेकिंग हॉलिडे शॉपिंग सीजन था और अमेजन के लिए 2023 एक मजबूत समापन था। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम 2024 में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी टीमें तेजी से प्रदर्शन कर रही हैं और हमारे सामने उत्साहित होने के लिए बहुत कुछ है।

जिला कलक्टर ने मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश

श्री अन्नपूर्णा रसोई का किया औचक निरीक्षण भोजन कर परखी गुणवत्ता, भोजन की क्वालिटी पर जताई संतुष्टि

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। जिला कलक्टर श्री नमित मेहता ने शनिवार को चंद्रशेखर आजाद नगर में श्री अन्नपूर्णा रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रसोई की भोजनशाला, भण्डार कक्ष, टोकन काउंटर तथा वहां साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलक्टर ने टोकन काउंटर पर नियुक्त स्टाफ से बात की तथा परोसी जा चुकी थालियों की जानकारी ली।

जिला कलेक्टर ने रसोई की भोजनशाला में तैयार किए गए खाद्य के आस पास सफाई देखी तथा स्वयं ने रसोई का भोजन कर गुणवत्ता की जांच की। जिला कलक्टर ने भोजन की क्वालिटी पर संतुष्टि जताई। जिला कलक्टर ने निर्धारित मात्रा अनुरूप थाली में परोसे जाने वाले भोजन के वजन की जांच भी की।

जिला कलेक्टर ने रसोई में भोजन कर रही महिला से बातचीत करते हुए रसोई में परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी के बारे में फीडबैक लिया। इस दौरान महिला ने बताया कि वह नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ही कार्य करती है तथा प्रतिदिन वहां भोजन करती है। महिला ने बताया कि यहां खाना रोज अच्छा बनता है और यहां अच्छे व्यवहार एवं सम्मान के साथ भरपेट भोजन करवाया जाता है। उसने सभी व्यवस्थाओं पर अपनी संतुष्टि जताई।

इस अवसर पर संकल्प सेवा संस्थान से रसोई संचालक अर्पित सोमाणी ने जिला कलक्टर को रसोई संबंधी जानकारी दी तथा संचालन में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। जिला कलक्टर ने रसोई में कार्यरत महिला ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों के व्यवधान के कारण श्री अन्नपूर्णा रसोई संचालन में समस्या का सामना करना पड़ता है, इस पर जिला कलक्टर ने संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए निर्देशित किया।

भोजन की गुणवत्ता एवं योजना में पारदर्शिता की हो नियमित मॉनिटरिंग

जिला कलक्टर ने जिला परियोजना अधिकारी श्री अमृत खोईवाल को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं योजना में पारदर्शिता की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा जो मात्रा बढ़ा दी गई है वह 600 ग्राम प्रत्येक थाली तक आवश्यक रूप से पहुंचाने के निर्देश प्रदान किए।

जिला कलक्टर ने जिला परियोजना

अधिकारी को रसोई में टाइल्स लगवाने के लिए निर्देशित कहा ताकि स्वच्छ तथा सुंदर वातावरण में व्यक्ति पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन कर सकें।

सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता हो सुनिश्चितः जिला कलक्टर

इसके पश्चात जिला कलक्टर श्री नमित मेहता ने शनिवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चंद्रशेखर आजाद नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ चिकित्सालय में आमजन को प्रदान की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र में उपस्थित मरीजों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। दवा काउंटर पर जाकर निःशुल्क दवा वितरण प्रणाली की जानकारी ली व प्रयोगशाला कक्ष, कोल्ड चेन कक्ष, वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिला कलक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक के पद रिक्त पाए जाने पर सीएमएचओ डॉ मुश्ताक खान को तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था कर इसके स्थाई समाधान के निर्देश दिए और कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं, साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा प्रदान दी जाने वाली समस्त सुविधाओं को समय पर मरीजों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

औचक निरीक्षण में पाई ख़ामियो को सुधारने के लिए ज़िला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। जहाजपुर उपखंड मुख्यालय स्थित चिकित्सालय, जेल, कृषि एवं शहरी नरेगा योजना का जिला कलेक्टर टीकम चन्द बोहरा ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। चिकित्सालय निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर टीकमचंद बोहरा ने आमजन को बिना परेशानी के चिकित्सा की सुविधा मिले, चिकित्सालय में साफ सफाई पर विभाग की ओर से विशेष ध्यान देने पर जोर देते हुए चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही नेत्र रोग विभाग एवं दंत रोग विभाग में पाई गई खामियों को दूर करने के एवं जल्द ही चिकित्सालय में ईसीजी व्यवस्था चालू करने के भी निर्देश दिए गए। चिकित्सालय परिसर में बना रहे डॉक्टर क्वार्टर्स के बारे में भी जानकारी ली एवं जल्द से जल्द गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने के लिए ठेकेदार से चर्चा की एवं चिकित्सालय परिसर में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक टीम गठित की गई जिसमें उपखंड अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, पीडब्ल्यूडी जयन शामिल होंगे। जो जांच कर जिला कलेक्टर को रिपोट करेंगे।

होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हरीश यादव ने जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान मरीज को सीएससी से होम्योपैथिक चिकित्सालय से दूरी होने के कारण जांच के लिए मरीज को हो रही परेशानी के बारे में जानकारी दी। इस पर जिला कलेक्टर ने आयुर्वैदिक हॉस्पिटल के पास पुरानी बैंक ऑफ़ बड़ौदा की बिल्डिंग में होम्योपैथिक चिकित्सालय शिफ्ट करने के लिए तहसीलदार एवं पंचायत समिति विकास अधिकारी को निर्देश दिए। चिकित्सालय परिसर से सटे कृषि विभाग का भी जिला कलेक्टर ने निरीक्षण कर कहा कि यह जगह पूरी चिकित्सालय परिसर में

शामिल कर चिकित्सालय परिसर को बड़ा बनाया जाएगा। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी लेखराज चौधरी से भी जिला कलेक्टर ने चर्चा की। एवं कृषि विभाग से सेट चाय की केबिन को हटाने के लिए नगर पालिका ईओ को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर बोहरा ने जेल का निरीक्षण किया जिसमें कैदियों से जेल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली एवं किस प्रकार जेल में आएं उस बारे मे जानकारी ली इस दौरान जेलर नारायण सिंह मौजूद थे। इस दौरान तहसीलदार राजीव बड़गुर्जर, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अशोक जाट, सीएससी डॉक्टर नईम अख्तर, डॉ पी एस गोयल, ब्लॉक प्रोग्राम अधिकारी रामजस मीणा मौजूद थे। नगर पालिका क्षेत्र में चल रही शहरी नरेगा योजना का भी जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया जिसमें | 30 में से 12 लेबर मौके पर मौजूद रहने, गैर हाजिर लेबर का नाम हटाने, मस्टरोल में कार्य करने के इच्छुक लोगों के ही नाम लिखने के लिए नगर पालिका कनिष्ठ तकनीकी सहायक को निर्देश दिए।

प्रथम विश्व ओड़िया सम्मेलन का उद्घाटनः मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वरः मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पहले विश्व ओड़िया सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्य मंच पर संस्कृति मंत्री अश्विनी पात्र , साहित्य डॉ. सीताकांत महापात्रा, डॉ. प्रतिभा राय और 5 अध्यक्ष भि के पांडियन मौजूद हैं ।प्रारंभ में संस्कृति सचिव सुजाता कार्तिकेयन ने स्वागत भाषण दिया ।उड़िया भाषा के प्रचार, संरक्षण और प्रसार के लिए आज से 'प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन' आयोजित किया जा रहा है। समसामयिक भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग की ओर से राजधानी के जनता मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है । आयुध मिट्टी से लेकर आकाश तक की सजावट से भरा हुआ है। हर कार्यक्रम को इस तरह से डिजाइन और व्यवस्थित किया गया है कि ओड़िया भावनाओं को

छुआ जा सके। राज्य सरकार ने विदेशों में रहने वाले ओड़िआ लोगों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए ऐसे प्रयास की सराहना की है ।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 3 से 5 फरवरी को विश्व ऑर्थोडॉक्स भाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है । भाषा अतीत का अस्तित्व है - भाषा भविष्य है। इसी मुद्दे के आधार पर राज्य सरकार ने सम्मालिनी की रूपरेखा तैयार की है । उड़िया भाषा के प्रत्येक अनुभाग को सारांश में स्थान दिया गया है। कुल 17 सत्रों में 100 से अधिक प्रसिद्ध भाषाविदों, बुद्धिजीवियों और विद्वानों के सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है।

इस अवसर पर देवीप्रसन पटनायक को उड़िया और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए 'प्रथम विश्व ओड़िया सम्मेलन सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ज्ञानपीठ, पद्म पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान और राज्य अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। 30वें दिन 11वें दिन बंदे में उत्कल जननी का गायन होना तय है । सरकार ने सम्मेलन के सभी कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया है ।आज मुख्यमंत्री ने स्मारक 'अक्षर धुरी' का उद्घाटन किया ।इस मौके पर राजधानी में भाषा के आधार पर 'एकता महोत्सव' का आयोजन किया गया है ।

क्षेत्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुनिबिल में पुरस्कार वितरण समारोह

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर्ः ओदिशा कि ढेंकनाल जिले के कामाक्षानगर ब्लॉक के अंतर्गत क्षेत्रीय उच्चतर माध्यमिक, गुनिबिल में नवीन, कामाक्षानगर, 29-1-24. एवं कार्यक्रम का ओरध्य साहित्य एवं श्रीजगन्नाथ संस्कृति से संबंधित चर्चा चक्र जापान स्कूल के चेयरमैन श्री शिशिर कुमार राऊत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । अपने भाषण में, अध्यक्ष ने राय व्यक्त की कि ओडिया साहित्य और श्री जगन्नाथ संस्कृति, ओडिशा की प्रगति और पहचान सिक्के के दो पहलू हैं, और छात्रों को अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने की सलाह दी। प्रोफेसर श्री निर्मल चंद्र मिश्र ने भगवान जगन्नाथ की महिमा और संस्कृति पर सारगर्भित भाषण दिया। मुख्य अतिथि श्री पुर्न् चंद्र मोहंती ने बच्चों को अपनी मिट्टी, भाषा और जगन्नाथ के प्रति प्रेम बनाये रखने की सलाह दी। अतिथि व्याख्याता श्री प्रसन्न कुमार नायक, गीता व्याख्याता श्री प्रमोद कुमार बराल और संजय कुमार ने ओडिशा की भाषा और संस्कृति पर अपनी बहुमूल्य राय दी। कार्यक्रम के 8 वर्गों में विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किये। अंत में नोडल अधिकारी प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर मोहंती ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक ब्रहमानंद दास, निरंजन स्वयम, अनिल कुमार स्वयम, प्रहलाद कुमार राऊत, किरानी प्रसन्न कुमार भोई, तोफान राऊत, रमेश नायक उपस्थित थे।

मदनपल्ले विधानसभा चुनाव में विद्रोही.. तैयार.

- आंध्र प्रदेश मदनपल्ले विधानसभा
- मल्लेला पवन कुमार रेड्डी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ।जाने का समय.?
- सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के लिए मशहूर मल्लेला फाउंडेशन...
- पूरे निर्वाचन क्षेत्र में भारी संख्या में प्रशंसकों।
- जगनमोहन रेड्डी के प्रति अनंत स्नेह।
- पूरे निर्वाचन क्षेत्र में YCP को मजबूत करने के प्रयास....
- मदनपल्ले विधानसभा की उम्मीदवारी के लिए अंतिम प्रयास....
- वह मैदान में स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत साबित कर रहा है

परिवहन विशेष न्यूज

मल्लेला पवन कुमार रेड्डी मल्लेला फाउंडेशन के मुखिया हैं जिन्होंने मदनपल्ले निर्वाचन क्षेत्र में सेवा कार्यक्रम किए हैं जो कोई और नहीं कर सकता....

मल्लेला फाउंडेशन सेवा कार्यक्रमों के लिए ब्रांड ...

मदद का पर्याय है मल्लेला फाउंडेशन....

मल्लेला फाउंडेशन के अध्यक्ष मल्लेला पवन कुमार रेड्डी जो मदनपल्ले निर्वाचन क्षेत्र में बदल गए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के बड़े प्रशंसक हैं, एक महान शक्ति जो लगातार वाईसीपी के लिए काम करती है ....

आगामी आम चुनाव में मदनपल्ले विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू....

अनुयायियों, शुभचिंतकों और मित्रों के साथ विचार विमर्श करते हुए कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर उनकी सेवाओं की कितनी पहचान है यह साबित करने का सही समय है....

अभियान चल रहा है कि पवन कुमार रेड्डी को ये आइडिया दिख रहा है कि मैं क्या हूँ, भविष्य में क्या करूँ, कैसे जाऊँ, यही समय है...

सेवा का प्रतीक है मल्लेला फाउंडेशन :-

मल्लेला फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो मदनपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में हर किसी के लिए जाना जाता है। मल्लेला फाउंडेशन मल्लेला के संस्थापक पवन कुमार रेड्डी ने पिछले दस वर्षों से कई सेवा कार्यक्रमों के साथ मदनपल्ले निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया है। सेवा की कोई परिभाषा नहीं होती... पवन कुमार रेड्डी द्वारा की गई सेवाओं का अंत नहीं होने पर मल्ला फाउंडेशन ने हर सोशल ग्रुप को कुछ मदद की है। Vwakthi Malela पवन कुमार रेड्डी, जिन्होंने एक अंतरंग यात्रा के माध्यम से अपनी उपलब्धियों के दर्द को जाना है। अपने आप को नेक दिल इंसान बता चुके पवन कुमार रेड्डी ने गांवों की समस्याओं की पहचान की। यह महसूस करते हुए कि बेरोजगारी अधिक है, वे उद्योग बनाने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, महिलाओं के लिए स्वरोजगार, गरीब छात्रों के लिए उच्च शिक्षा, और एससी, एसटी, बीसी, अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर समाज और हर

गरीब की किसी न किसी तरह मदद की गई है। लेकिन हर परिवार की मदद करने के लिए जन प्रतिनिधि बनना संभव है, सभी निर्वाचन क्षेत्र वासियों की तरफ से विधायक बनना, ताकि वो जो चाहे कर सके और जनता के साथ जुड़ सके।

मल्लेला पवन कुमार रेड्डी एक किसान परिवार में पैदा हुए रत्न हैं :-

मल्लेला पवन कुमार रेड्डी का अपना गांव रामसमुद्रम मंडल एलकपल्ली बड़े किसान परिवार में पैदा हुए पवन कुमार रेड्डी ने उच्च शिक्षा की पढ़ाई की। बैंगलोर में रहकर उन्होंने व्यवसाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कई ट्रेडों में अनुभव के साथ, एक व्यवसायी और उद्यमी के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करें। जिस जगह पैदा हुए और पला-बढ़ा वहाँ के लिए कुछ करने के विचार से 2014 से लेकर अब तक मदनपल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई सेवा कार्यक्रम किए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, मंदिरो का विकास, युवाओं के लिए खेल कौशल, गरीबों को भूख खिलाने, महिलाओं के सांस्कृतिक व पारंपरिक कार्यक्रम, ऑटो वर्कर्स परिवारों को वस्त्र वितरण, संक्रान्ति के दिन आवश्यक वस्तुओं का वितरण, रमजान पर्व और कई अन्य कार्यक्रम किए गए हैं। विशेष रूप से निर्वाचन क्षेत्र के निम्मानापल्ली, रामसमुद्रम, मदनपल्ली ग्रामीण मंडलों में मदनपल्ली शहर में हजारों गरीब छात्रों को नोटबुक और शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। मदनपल्ली जेड पी हाई स्कूल में विशाल स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता टीमों को प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण किया गया। मदनपल्ली जेड पी हाई स्कूल में महिलाओं के लिए ट्रायथलॉन प्रतियोगिताएं करवाई गई। विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी मेले, तिरुनाल लगे तो वहां भाग लेने वाले श्रद्धालुओं, गरीबों, यात्रियों और भिखारियों के लिए भारी मात्रा में अन्नदान का आयोजन किया गया। लाखों लोगों के मुख से पवन कुमार रेड्डी को बधाई और आशीर्वाद दिया। किसी भी गांव में पुराने मंदिर नए बनवाये और नए मंदिर बनवाये बहुत आर्थिक मदद की गई है। मदनपल्ले नगर में ऑटो क्षेत्र पर आश्रित परिवारों को नए कपड़े वितरित किए गए। हिन्दू मुस्लिम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रमजान और संक्रान्ति के दिन गरीबों को आवश्यक सामान वितरित किया गया। शादी करने वाले गरीब जोड़ों को थमा और नए कपड़े। मल्ला पवन कुमार रेड्डी द्वारा मदनपल्ले निर्वाचन क्षेत्र में की गई सेवाओं को अमूल्य बताया जा सकता है।

पसंदीदा नेता जगनमोहन रेड्डी :-

YCP नेता जननेता मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यानी मल्लेला पवन कुमार रेड्डी का स्नेह अनंत है। उनके नक्शेकदम पर चलते हुए, वाईसीपी को मजबूत करने के लिए अपना खुद का धन खर्च किया और जनता के बीच 2019, 2024 विधानसभा चुनाव में मदनपल्ले ने YCP उम्मीदवारी की थी। वाईसीपी वर्चस्व ने मल्लेला पवन कुमार रेड्डी को दो बार जिद्दी हाथ दिखाया है। दो साल पहले मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के जन्मदिन के अवसर पर बैंगलोर से मदनपल्ले आकर हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा कर मनाया था। गत वर्ष भी वृहद स्तर पर अन्नदान कार्यक्रम हुए थे। पवन कुमार रेड्डी की मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से काफी निकटता है। मुख्यमंत्री के दर्जा में भी पवन वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बिना अपॉइंटमेंट सीधे मिल जाते। निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ा निम्न समूह है। खासकर युवाओं, महिलाओं, जैस्मीन के शौक़ीन बहुत सारे लोग हैं। मदनपल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो भी सुनेगा चमेली के शब्द ही सुनेगा। इतने लोकप्रिय पवन कुमार रेड्डी वाईसीपी में मान्यता के अभाव में बेहद असहज हैं।

आजाद प्रत्याशी के रूप में बाड़ी में प्रवेश की तैयारी :-

कुछ राजनीतिक कारणों से वाईसीपी वर्चस्व ने मदनपल्ली विधायक की उम्मीदवारी को दो बार उपेक्षित किया है। निसार अहमद को प्रभारी घोषित किया गया है। इस पृष्ठभूमि में वे वाईसीपी से दूर रहकर चुप रह रहे हैं। मदनपल्ली विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चर्चा होगी पवन कुमार रेड्डी कहाँ होंगे, कहाँ कदम उठाएंगे और क्या रणनीति है। नव वर्ष के अवसर पर मदनपल्ले नगर में थिंक नाम से फ्लेक्सिस लगाया गया है..

अगर रेड्डी समुदाय एक साथ आता है तो ऐसा है जैसे पवन कुमार रेड्डी कामयाब हो गया है :-

मदनपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में रेड्डी सामाजिक समूह के वोट महत्वपूर्ण हैं। प्रचार चल रहा है कि वाईसीपी मल्लेला पवन कुमार रेड्डी का समर्थन करने वाले रेड्डी सोशल ग्रुप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर पूरा समर्थन करेंगे। प्रचार किया जा रहा है कि पवन कुमार रेड्डी के साथ नहीं चल रहे कुछ मजबूत नेता मजबूत करने को तैयार हैं। ये खुला राज है कि मदनपल्ले YCP में पिछले पांच सालों से रेड्डी समुदाय का अपमान हो रहा है। भले ही यह प्रचार किया गया कि इस बार निश्चित रूप से रेड्डी सामाजिक जाति के व्यक्ति को मैदान में लाएंगे, लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यको के लिए आवंटन पर वे बहुत नाराज थे। पवन कुमार रेड्डी ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में करके आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने की कोशिश शुरू कर दी है।

पवन कुमार रेड्डी मैदान में उतरे तो YCP को झटका लगेगा...

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मल्ला पवन कुमार रेड्डी अगर आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे तो वाईसीपी को निश्चित रूप से बड़ा झटका लगेगा। पवन कुमार रेड्डी जो एक मजबूत रेड्डी समुदाय से संबंध रखते हैं समाज सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है। मुख्य रूप से YCP को मजबूत करने के लिए काम किया। वाई सी पी उच्च नेतृत्व चाहते हैं कि उन्हें विधानसभा चुनाव में मदनपल्ले उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। सीएम जगनमोहन रेड्डी के लिए वाईसीपी नेता के रूप में भारी मात्रा में फ्लेक्सिस की व्यवस्था की गई है। इस पृष्ठभूमि में पवन कुमार रेड्डी ने वाईसीपी मतदाताओं को प्रभावित किया है। सेवा कार्यक्रमों के साथ-साथ YCP को YCP नेता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यह अभियान जारी है कि अगर वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े तो YCP वोट उनकी तरफ बढ़ जाएंगे। विशेष रूप से जन मतदाताओं के लिए पवन कुमार रेड्डी ने संपर्क किया है। दीमा मल्लेला फाउंडेशन टीम के सदस्यों में देखा जा रहा है कि लाभार्थी एक भी वोट दे तो पवन कुमार रेड्डी जरूर जीतेंगे...

शमीम असलम दूसरी बार आंध्र प्रदेश खनिज विकास के अध्यक्ष बने

आंध्र प्रदेश मदनपल्ले के गुंदलुरी शमीम को एक बार फिर मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री आशाखा में उनकी सेवाओं को मान्यता देते हैं। जगन ने उसे फिर से दे दिया है। अतीत में, वह उसी पद पर बनी रही है, और उनके कार्यकाल के अंत में उन्हें फिर से मौका दिया गया था। सी ने उस पर विश्वास के साथ इस्तीफा दे दिया। वाई एम। सांसद जगन को समीम ने मिथुन रेड्डी, मंत्री पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी का धन्यवाद किया।

अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा जमीयत, पदाधिकारी बोले- फैसला पूरी तरह गलत, हमारा पक्ष सुना नहीं गया

ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट पर बात न सुनने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि इस मामले में जल्द राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे। शुक्रवार को दिल्ली के जमीअत उलमा ए हिन्द कार्यालय में मुस्लिम पक्ष की बैठक हुई।

नई दिल्ली। बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि कोर्ट में हमें अपनी बात तक रखने का मौका नहीं दिया गया। जिस तरह से तहखाने में पूजा शुरू करवा दी गई वह प्रशासन के कार्य पर सवाल उठाता है। अदालत ने प्रशासन को इस काम के लिए सात दिन का समय दिया था। उन्होंने कहा कि वाराणसी जिला न्यायाधीश के फैसला पर हैरानी है। यह फैसला गलत और निराधार है। तहखाने में कभी भी पूजा नहीं हुई थी, एक निराधार दावे को बुनियाद बनाकर जिला जज ने सेवा के अंतिम दिन आपत्तिजनक फैसला दिया। हिंदू पक्ष ने गलत तथ्यों का आधार बनकर मामले पेश किया जिससे समाज में माहौल खराब हो गया है। हालांकि अभी अदालत में न तो इस पर कोई बहस हुई है और न ही उस की पुष्टि। यह रिपोर्ट महज एक दावा है। उन्होंने कहा कि जिला अदालत को भी मुस्लिम पक्ष को अपील का मौका देना चाहिए था जो कि उस का कानूनी अधिकार है। समस्या केवल ज्ञानवापी मस्जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरह मथुरा की शाही ईदगाह, दिल्ली की सुनहरी और अन्य मस्जिदों से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि यदि इसी तरह से सब चलता रहा तो देश में कही भी विवाद खड़ा होगा और इसमें मुस्लिम पक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी। इस मौके पर जमीअत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सय्यद असद महमूद मदनी, जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष जनाब मलिक मोतसिम खान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023